राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारित

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
YouTube Linked in
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of
India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण गुरूवार 22अक्टूबर2020 वर्ष-3, अंक -266 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत ने चीन को उसका सैनिक लौटाया, LAC पार कर आ गया था लद्दाख

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने चीन को उसके सैनिक को लौटा दिया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर लद्दाख आ गया था। कल रात चुशूल मोल्दो में बैठक स्थल पर चीनी सेना के कॉर्पोरल वांग हां लॉन्ग को चीनी सेना को सौंप दिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसका एक सिपाही रविवार रात को सीमा के पास से लापता हो गया। चीन ने भारतीय सेना से प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने सैनिक को लौटाने की गुहार लगाई थी। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में सोमवार को पकड़ा है, जिसकी पहचान कर्नल के रूप में हुई है।

चीन ने कहा था- याक की खोज में सीमा पार हुआ, प्लीज लौटा दें

पश्चिमी थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने सोमवार रात को लापता पीएलए सैनिक पर एक बयान जारी किया और कहा कि हमारा एक चीनी सिपाही उस वक्त लापता हो गया, जब वह 18 अक्टूबर की रात एक चरवाहे को अपना खोए हुए याक को खोजने में मदद कर रहा था। हालांकि, उन्होंने अपने सैनिक की पहचान नहीं की है। पश्चिमी थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग ने बयान में आगे कहा कि घटना के तुरतं बाद ही चीनी सीमा रक्षकों ने भारतीय पक्ष को घटना की सूचना दे दी थी और उम्मीद जताई कि भारतीय पक्ष चीनी सैनिक को खोजने और उसे रेस्क्यू करने में मदद करेगा।

देश में पहले फेज में 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार के पास खाका तैयार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर अपने ढलान पर दिख रहा है और इस बीच सरकार भी कोरोना की वैक्सीनेशन (टीकाकरण) को लेकर पूरी तैयारी में दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रलाय के अधिकारियों की मानें तो देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन-किन लोगों को दिया जाएगा, सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले फेज में देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाने वाले 3 करोड़ (30 मिलियन) लोग कौन होंगे, सरकार इसका खाका तैयार कर चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स मसलन डॉक्टर्स, हेल्थकेयर स्पेशलिस्ट, पुलिस और सैनिटेशन कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन पाने वाले 30 मिलियन (3 करोड़) में 7 मिलियन डॉक्टर और पैरामेडिक्स शामिल हैं और 20 मिलियन अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के पास पहले से ही 30 मिलियन आबादी का टीकाकरण करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। हमारे पास कोल्ड चेन, शीशियां, सीरिंज और सब कुछ है।

बता दें कि देश में अभी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले साल के शुरुआत में वैक्सीन देश में उपलब्ध हो सकती है। यही वजह है कि जनवरी और जून 2021 के बीच टीकाकरण का पहला चरण अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है।

कुछ निजी अस्पतालों ने दावा किया कि उनके पास कोविड-19 वैक्सीन की बड़ी खुराक को स्टोर करने और रख-रखाव करने के लिए बुनियादी ढांचा है, इस पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार निजी संस्थाओं के साथ भी तालमेल बिठा रही है। भूषण ने कहा कि हमारे पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर एक मौजूदा इन्वेंट्री भी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए हम अपनी इन्वेंट्री का उपयोग करेंगे।

पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार भी लाएगी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी और इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की मंगलवार शाम को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्री परिषद ने राज्य के किसानों के हित में यह निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए।

गहलोत ने ट्वीट किया, आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध विधेयक पारित किये हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा।%% बयान के अनुसार, राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही, व्यापारियों द्वारा किसानों की

फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए दीवानी अदालत के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की।

मंत्री परिषद का मत है कि राजस्थान में ऐसे प्रकरणों में फसल खरीद के विवादों के मण्डी समिति या दीवानी अदालत के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत रहनी चाहिए।

मंत्री परिषद ने माना कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न कृषि जिन्सों के भंडार की अधिकतम सीमा हटाने से कालाबाजारी बढ़ने, अनाधिकृत भण्डारण तथा कीमतें बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि अनुबंध कृषि अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखना प्रदेश के किसानों के हित में होगा।

पंजाब में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक

पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी थे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में तीन विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि कोई किसानों को रस्क्क से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

मदरसों के आधुनिकीकरण पर पेशेवर तरीके से आगे बढ़ेगी सरकार, औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश होगी तेज

नई दिल्ली। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार पेशेवर तरीका अपनाएगी। सरकार की कोशिश है कि यह काम सरकार और मुसलिम समाज मिल कर करे। इसके लिए सरकार मदरसा से जुड़े लोगों की भी राय लेगी। ताकि, किसी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने इस तरह की रिपोर्ट बनाने वाली विभिन्न एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसियां इस बारे में सभी की राय लेंगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर तमाम तरह के सुझाव आ रहे हैं। कई लोगों ने मदरसों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। पर हमारी कोशिश है कि इस बारे में पूरे अध्ययन और सभी के साथ आगे बढ़ा जाए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी मदरसे से जुड़े लोगों से भी बात कर मदरसों के आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा कर उनकी राय को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार मदरसों को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार मदरसों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करती रही है। मंत्रालय का कहना है कि मदरसों के बारे में पेशेवर राय लेने का मकसद इनमें पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। ताकि, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी दूसरे स्कूलों के विद्यार्थियों की तरह अवसर मिल सके। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे औपचारिक शिक्षा हासिल करें और राज्य व दूसरे बोर्ड के इम्तिहान में बैठें। इसके साथ हम मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।

रेलवे की मनमानी, पर्व स्पेशल और क्लोन ट्रेनों में यात्रियों से वसूल रहे 30 फीसदी अधिक किराया

पटना। त्योहार के समय आम लोगों को राहत देने के लिए रेलवे की ओर से क्लोन स्पेशल व पर्व स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले की तुलना में 25 से 30 फीसदी अधिक किराया देना पड़ रहा है। जबकि इन ट्रेनों में अमूमन सामान्य व मध्यम वर्ग के यात्री ही आ-जा रहे हैं।

पर्व स्पेशल ट्रेनों में पटना से नई दिल्ली के लिए स्लीपर क्लास के लिए 650 रुपये लग रहे हैं, जबकि दूसरी ट्रेनों में पटना से नई दिल्ली का किराया महज 510 रुपये है। इसी तरह सभी पर्व स्पेशल ट्रेनों में पहले से चल रही ट्रेनों की तुलना में 30 प्रतिशत तक अधिक किराया वसूला जा रहा है।

क्लोन ट्रेनें भी चलायी जा रहीं

पटना जंक्शन के आरक्षण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या कम होने व यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने पर्व स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

ऐसे लिया जा रहा अधिक किराया

	स्पेशल ट्रेन			पर्व स्पेशल		
स्थान	स्लीपर	3 एसी	2 एसी	स्लीपर	3 एसी	2 एसी
नई दिल्ली	510	1300	1910	650	1710	2320
मुंबई	670	1795	2600	920	2315	3225
बेंगलुरु	910	2355	3435	1095	2745	3885
सिकंदराबाद	745	1945		845	2205	
हावड़ा	350	915	1280	435	1165	1615

जिन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो रही थी, उसके लिए क्लोन ट्रेनें चलाई गई हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल व पाटलिपुत्र जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों से अभी कुल 60 जोड़ी पर्व व क्लोन स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इन ट्रेनों में सफर करने वालों की जेबें ढीली हो रही हैं।

पर्व स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी, 3 एसी और 2 एसी में प्रति टिकट 150 रुपये से लेकर 450 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। वहीं, पटना से मुंबई के लिए पर्व स्पेशल व क्लोन ट्रेनों में शयनयान श्रेणी के लिए 920 रुपये लग रहे हैं, जबकि दूसरी ट्रेनों में इसका किराया 670 रुपये है। यानी एक यात्री से प्रति टिकट 250 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु के लिए पर्व स्पेशल के स्लीपर क्लास का टिकट दूसरे ट्रेन की तुलना में 185 रुपये अधिक है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे मनमाने ढंग से यात्रियों से पैसे की वसूली कर रहा है। रेलवे व सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं है।

पूर्व मध्य रेल में 60 जोड़ी क्लोन-पर्व स्पेशल ट्रेन

पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेल में मंगलवार से कुल 48 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। इसमें से पूर्व मध्य रेल की ट्रेन के अलावा फॉरेन ट्रेन व पासिंग ट्रेनें शामिल हैं। वहीं, 12 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी हो रहा है। पर्व स्पेशल में 13 जोड़ी ट्रेन पूर्व मध्य रेल की है। 18 जोड़ी ट्रेनें दूसरे जोन की हैं जो यहां के स्टेशनों पर पहुंचेंगी व खुलेंगी। वहीं, 17 जोड़ी ट्रेनें पासिंग हैं जिनका केवल पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों पर ठहराव होगा। वहीं, पांच जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेल व पांच जोड़ी फॉरेन की हैं। दो जोड़ी पासिंग ट्रेनें हैं।

दिसंबर में मिल सकती है मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी

वाशिंगटन। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्टीफन बैंसेल ने कहा कि अगर नवंबर में वैक्सीन के तीसरे चरण के मानव परीक्षण का सकारात्मक परिणाम सामने आ जाता है तो अमेरिकी सरकार दिसंबर में इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। मंगलवार को बैंसेल ने एक समाचार पत्र के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तीसरे चरण के परीक्षण का पयार्प्त अंतरिम परिणाम आने में देर होगी तो अगले साल तक वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं है। मॉडर्ना ने जुलाई में 30000 वालंटियर पर तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू किया था। परीक्षण के दौरान 50 फीसदी वालंटियर को वैक्सीन का डोज दिया गया और शेष वालंटियर को प्लैसेबो दिया गया। कंपनी के सीईओ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के प्रभाव को जांचने वाली इसकी पहली विश्लेषण रिपोर्ट नवंबर में आ सकती है लेकिन यह कब तक आयेगी यह सुनिश्चित नहीं है। दरअसल पहली अंतरिम विश्लेषण रिपोर्ट इस आधार पर तैयार होती है कि पूरे परीक्षण के दौरान 53 वालंटियर लक्षण वाले कोरोना संक्रमित हुये या नहीं। अगर इन 53 लोगों में वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों की संख्या प्लैसेबो लेने वाले व्यक्तियों से उल्लेखनीय रूप से कम हुई तो कंपनी फिर वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। कंपनी के सीईओ ने बताया कि अगर पहले अंतरिम विश्लेषण में वैक्सीन का प्रभाव पयार्प्त नहीं रहा तो वह दूसरा विश्लेषण तब करेगी, जब 106 वालंटियर में संक्रमण के लक्षण दिखायी देंगे। इसमें दिसंबर तक का समय लग सकता है और तब ऐसी स्थिति में अगले साल जनवरी के अंत तक या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में मंजूरी मिल सकती है। बैंसल ने बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, यह पता करने के लिए उसे परीक्षण में शामिल कम से कम 50 फीसदी वालंटियर की सुरक्षा की दो माह तक निगरानी करनी जरूरी है और तब ही वह आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकती है। इस काम के भी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर मॉर्डना तत्काल इसके बाद आवेदन कर देती है तो आवेदन की जांच करने में कुछ सप्ताह लगेंगे और फिर दिसंबर में निर्णय सामने आ जायेगा।

रक्षा प्रमुख के संग अमेरिकी विदेश मंत्री आएंगे भारत, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अगले सप्ताग नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और वहां के रक्षा प्रमुख माइक इस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ चर्चा के लिए 27 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं।

सचिव इस्पर ने एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में आगामी 2 + 2 के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सचिव पोम्पियो और वह अगले सप्ताह भारत जाएंगे। उन्होंने यह भी पूछा, ÷यह भारतीयों के साथ हमारा दूसरा 2+2 बैठक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लिए तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।

उन्होंने कहा, भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होगा। मुझे लगता है कि इंडो-पैसिफिक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक बहुत ही सक्षम देश है। यहां बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। हर दिन हिमालय में चीनी आक्रामकता विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण की रेखा के साथ देखने को मिल रही है।

सचिव इस्पर ने एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में आगामी 2 + 2 के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सचिव पोम्पियो और वह अगले सप्ताह भारत जाएंगे। उन्होंने यह भी पूछा, यह भारतीयों के साथ हमारा दूसरा 2+2 बैठक है।

भारत और अमेरिका के बीच यह तीसरी 2+2 बैठक होगी। भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 2019 में वाशिंगटन डीसी में यह चर्चा हुई थी

भारत-अमेरिका के संबंध किसी राजनीतिक दल से काफी बड़े हैं

अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध किसी राजनीतिक दल से काफी बड़े हैं तथा दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को यहां दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है।

भारत और बांग्लादेश की हाल में यात्रा करनेवाले अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन ई बीगन ने कहा कि अमेरिका-भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, उसने अपने पूर्ववर्ती से विरासत में मिले संबंधों को बेहतर स्थिति में छोड़ा है और यह एक अद्भुत धरोहर है। बीगन अमेरिकी विदेश विभाग के लंदन रीजनल मीडिया हब द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संबंध किसी राजनीतिक दल से काफी बड़ा है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की इस टिप्पणी का काफी महत्व है क्योंकि यह ऐसे समय आई है जब कुछ दिन बाद तीन नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

विसंगतियों का चुनाव

विधानसभा चुनाव राज्यों के सिर्फ राजनीतिक रुझान का पता नहीं देते, वे उनके सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने, नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता और आर्थिक हालात से भी देश-दुनिया को रूबरू कराते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ सात दिन रह गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपने जन-संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों से जुड़ा एक तथ्य बिहार की विडंबना को गहराई से उजागर कर रहा है। इन 71 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा पेश किया है, उसके मुताबिक, 153 उम्मीदवार करोड़पति हैं और वे एक करोड़ से लेकर 53 करोड़ की मिल्कियत के मालिक हैं। दोनों मुख्य गठबंधनों ने बड़ी तादाद में करोड़पतियों में भरोसा जताया है। एनडीए के जहां करीब 60 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं, तो वहीं महागठबंधन के 58 फीसदी। ये आंकड़े सोचने को बाध्य करते हैं कि चंद महीने पहले जिस प्रदेश के लाखों लोग गरीबी के कारण पैदल ही अपने गांव के लिए सड़कों पर निकले पड़े थे, उसके नुमाइंदे कितने 'संपन्न' लोग होंगे!

एक दौर था, जब देश चिंतित हो उठा था कि हमारी विधायी संस्थाएं बाहुबलियों और दागी लोगों का अखाड़ा बनने लगी हैं, मगर उसकी इस बेचैनी को शासन-व्यवस्था ने समझा और स्थिति पर लगाम लगाने के वैधानिक तरीके भी निकाले गए। इसकी वजह से कई सारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित हुए, कई की सदस्यता रद्द हुई, मगर न्यायिक-प्रक्रिया की शिथिलता के कारण आज भी बड़ी संख्या में दागी चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अब नई चुनौती धनबल के रूप में खड़ी हो रही है। निस्संदेह, धनाढ्यों को भी राजनीति में आने, अवाम की सेवा करने का पूरा-पूरा अधिकार है। ऐसी नजीरें हैं कि आजादी के बाद कई लोगों ने अपनी दौलत लुटाकर जनसेवा के पथ को चुना था। मगर वह दौर काफी पीछे छूट चुका है। जो अनुपात अब दिख रहा है, वह एक किस्म के सामाजिक असंतुलन को अधिक प्रतिबिंबित करता है। बिहार की ही नजीर लें। जिस राज्य की सालाना प्रति-व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से एक तिहाई से भी कम हो, वहां की राजनीति में आर्थिक रूप से संपन्न तबके का दबदबा स्थापित हो जाए, तो यह स्थिति जनतंत्र से ज्यादा धनतंत्र की ताकत को दर्शाती है। हमारी सरकारी नीतियों में जन-संवेदनशीलता की कमी के पीछे बड़ी वजह यह भी है।

बिहार से आए इन आंकड़ों का एक गौरतलब पहलू यह भी है कि राज्य के जिन इलाकों में ये 71 सीटें हैं, वे एक लंबे समय तक सामंती उत्पीड़न, नक्सली हिंसा की जद में रहे हैं और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल वाम पार्टियां इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा मजबूती से लड़ भी रही हैं। मगर यह परिदृश्य गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन की मांग करता है कि बिहार में आर्थिक विषमता की खाई घटी है या बढ़ी है? आखिर क्यों बिहार के ज्यादातर नेता तो करोड़पति हैं, मगर उनके मतदाता पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर? इसमें कोई दोराय नहीं कि बिहार महिलाओं के लोकतांत्रिक सशक्तीकरण में देश में अग्रणी भूमिका में है। पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार काफी अधिक तादाद में महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। फिर इस सूबे की आर्थिक छवि क्यों नहीं बदल रही?

प्रदूषण से जंग

प्रदूषण की मार से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) त्रस्त है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह वायु की शुद्धता घट रही है्र उसने कइयों की चिंता बढ़ा दी है। पहले पराली जलाने की घटना से जिस तरह वातावरण दूषित हुआ्र उससे प्रदूषण को रोकने की सरकार की मुहिम को जोरदार झटका लगा है। आमतौर पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवम्बर में बढ़ती है, मगर इस बार प्रदूषण के पहले दस्तक देने से हर कोई हलकान है। चूंकि कोरोना के कारण पहले से ही सांस की बीमारी वाले मरीज बेहद चिंतित हैं्र ऊपर से जहर भरी हवा के कारण किसी को इसका समाधान नहीं सूझ रहा है और आनन-फानन में फिर से वही पारंपरिक उपाय मसलन ऑड़-ईवन शुरू करने के साथ-साथ निर्माण कार्यों को बंद रखना, इफट-भट्ठों पर पाबंदी शुरू करने की रणनीति बनाई जाने लगी है। वर्षों से जनता के जिगर में जहर घोल रहे इस विनाशकारी मर्ज का कोई ठोस उपाय नहीं तलाशा जा रहा है। देखने में आया कि पिछले दिनों कुछ निर्माण कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, मगर बात बनती नहीं दिख रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार या अन्य संस्थाओं ने प्रयास नहीं किए। चूंकि सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा कातिलाना हो जाती है इसलिए ऐसे वक्त में ज्यादा नियोजित तरीके से प्रदूषण पर चोट करने की जरूरत है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच समन्वय नहीं है। ऐसे महद्मवपूर्ण मसले पर भी दोनों के बीच विवाद से प्रदूषण से लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा हो भी रहा है। तल्खी के कारण तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। इसका खमियाजा निश्चित तौर जनता को भुगतना पड़ा रहा है। यह तर्क भी बेमानी सा लगता है कि प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है। जब धान की कटाई के बाद ही प्रदूषण बढे् और यह पराली जलाने की वजह से हो्र तो किसी को शक क्यों होता है? वाहन और अन्य निर्माण कार्य तो बाकी महीनों में भी होते हैं्र इसलिए सभी को पराली न जले; इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हालांकि किसान पराली नहीं जलाएं, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कई पॉलिसी लेकर आई, किंतु किसानों में इसे सकारात्मक रूप से नहीं लिया गया। अब एक बार फिर से प्रदूषण के खिलाफजंग के लिए हर किसी को तैयार रहना होगा।

चौं रे चम्पू/अशोक चक्रधर

दूषण-प्रदूषण असुर प्राणहंता

चौं रे चंपू! घर में जच्चा-बच्चा सब ठीक?

-सब कुशल है! घर में सवा महीने का नवजात मोहक शिशु है। मेरी विदुषी नृत्यांगना बेटी, अभी नृत्य तो कर नहीं सकती, उसके साथ सारगतभत बातें होती रहती हैं।

-हमैंऊ सार की बात बताय दै! -आप स्वयं अनुभवी हैं! उसका कहना था कि मां बनने का अनुभव कुछ ऐसा ही है जैसे आम धारणा में देवी को देखा जाता है। या तो ममत्व से परिपूर्ण सुशीला या काली चंडालिका जो संहार करती है। काफी बायपोलर अनुभव है। जीव-जंतुओं में लगभग सभी मादाओं को बच्चा पैदा करने की क्षमता देकर कुदरत ने गढ़ा है। जो चीज इतनी सार्वभौमिक है, वो पता नहीं कैसे मानव-जाति में बहुत ही पर्सनल और यूनिक बना दी जाती है। बच्चा पैदा करने वाली प्रारंभ से अपने साथ भावनाओं का उतार-चढ़ाव लेकर आती है। कभी उल्लास तो कभी डर। बहुत अजीब सी बात है कि आशा और एक्साइटमेंट की भावना, कितनी जल्दी थकावट और प्रसवोपरांती अवसाद में बदल जाती है। फिर कहने लगी्र ये महीना देवी के आने का है और यही महीना दिल्ली में प्रदूषण को आते हुए देखता है। देवी नौ दिन तक हमारे ङ्दय में निवास करती हैं और दसवें दिन अपने दिव्य-लोक में लौट जाती हैं, लेकिन प्रदूषण की दूषित हवा तो पांच महीने तक हमारे फेफड़ों में निवास करती है। इस बार मैं देवी से करजोड़ प्रार्थना करती हूं कि इस मानव-जाति को कुछ सुद्धि मिले, दूषित तद्मवों का संहार हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो और प्रदूषण दैत्य का वध हो, ताकि मेरा प्यारा नवजात शिशु और ऐसे ही हजारों बच्चे जो हर रोज पैदा होते हैं, दूषित और जहरीली हवा, उनकी उम्र कम न करे। चचा्र फिर उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने उसकी एक भरतनाट्यम नृत्य-संरचना के लिए एक संस्कृतनिष्ठ श्लोकावली लिखी थी। सुनाऊं?

-सुनाय दै मोहक के नाना! -त्रिपुर सुंदरी भैरवी छिन्नमस्ता! भुवनेश्वरी कष्ट-हरिणी समस्ता। कमला कदंबित-गृहेऋिद्ध-सिद्धी। पर्यावरण वायु-जल पूर्ण शुद्धी। धूमावती मुष्टिका मंत्र-मारण, काली-कपाली करो खड्ग धारण! दूषण-प्रदूषण असुर तीद्रणदंता! विकल प्राणियों को हुआ प्राणहंता। मातंगि बगला विकट रूप तारा! त्रिपुर-षोडशी कर प्रहारा-प्रहारा!

मदद और सम्मान मांगती ईमानदारी

जयंतीलाल भंडारी

ऋण चुकाने में ईमानदारी को प्रोत्साहन देने की ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के कारण लागू मोरेटोरियम के दौरान जिन ऋणधारकों ने अपनी ईएमआई किस्तों का ईमानदारी से भुगतान किया है, उन सभी को दिवाली के पहले कुछ विशेष वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। ऋण चुकाने के मोर्चे पर सुधार की दिशा में उठाया जा रहा यह बेहतरीन कदम है, बल्कि इससे कुल ऋण बाजार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आम तौर पर देखा यह गया है कि कर्ज न चुकाने वालों को ही रियायत देने के बारे में सोचा जाता है, लेकिन ऋण चुका रहे लोग भुला दिए जाते हैं।

इन दिनों एक ओर, केंद्र सरकार 2 नवंबर से पहले चक्रवृद्धि ब्याज माफी का लाभ छोटे कर्जदारों को देने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर, बैंकों ने भी अपने बही-खातों में कर्ज संबंधी अतिरिक्त प्रावधानों को आगे बढ़ाया है। एक ऐसे समय में, जब मोरेटोरियम यानी ऋण स्थगन को अपनाने वाले कर्जधारकों को लाभ दिया जा रहा है, तो जिन कर्जधारकों ने ऋण स्थगन को नहीं अपनाया है, उन्हें भी ईमानदारीपूर्वक नियमित ऋण भुगतान के एवज में लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए। ये लाभ ऐसे होने चाहिए, ताकि सबको असर या फायदा दिखे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक-दो किस्त की माफी से इस प्रोत्साहन को ज्यादा बल नहीं मिलने वाला। प्रोत्साहन ऐसा होना चाहिए कि उसका तात्कालिक असर हो और ईमानदारी से ऋण चुकाने वालों की तादाद बढ़े। ऋण क्षेत्र में ईमानदारी के साथ ही केंद्र सरकार को कर भुगतान के क्षेत्र में भी ईमानदारी को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए।

> जो लोग समय से ऋण चुकाते हैं, पूरा आयकर भरते हैं, देश में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार और संस्थाओं को हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार द्वारा ईमानदार करदाताओं के साथ न्यायसंगतता के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन कदमों का प्रचार होना भी जरूरी है। नवीनतम कानूनों ने कर-प्रणाली में कानूनी बोझ को कम कर दिया है। 'विवाद से विश्वास' योजना जैसी पहल ने अधिकांश मामलों को अदालत से बाहर निपटाने का मार्ग प्रशस्त किया है, कर स्लैब को भी मौजूदा सुधारों के एक हिस्से के रूप में युक्तिसंगत बनाया गया है, लेकिन अभी भी करदाताओं के पक्ष में ईमानदार पहल की जरूरत है।

भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। उल्लेखनीय यह भी है कि पिछले छह वर्षों में आयकर जांच के मामलों में कोई चार गुना कमी आई है। यह करदाताओं पर सरकार के भरोसे का प्रतिबिंब है। वर्ष 2012-13 में जांच की संख्या 0.94 प्रतिशत थी, जो घटकर 2018-19 में 0.26 प्रतिशत तक आ गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जीएसटी से देश में ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है तथा उद्योग-कारोबार जगत के सुझावों से इसमें लगातार सुधार भी किए जा रहे हैं। इसका बड़ा लाभ देश के ईमानदार कारोबारियों को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं।

हाल ही के महीनों में आयकर व्यवस्था के तहत कई ऐतिहासिक सुधारों को अमलीजामा पहनाया गया है, इनमें करदाता चार्टर, पहचान रहित अपील और पहचान रहित समीक्षा जैसे बड़े सुधार शामिल हैं। अब करदाता चार्टर के लागू होने से आयकर विभाग अपने दायित्वों के लिए पूरी तरह जवाबदेह है और विभाग के काम से संतुष्ट नहीं होने पर करदाता प्रत्येक क्षेत्र में गठित किए गए विशेष प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अब ईमानदार करदाताओं के मद्देनजर कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यह पाया गया है कि बहुत सारे लोगों द्वारा अच्छी आमदनी के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में, उनके कर नहीं देने का भार ईमानदार करदाताओं पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, देश की 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, यह संख्या बहुत कम है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2018 में बजट भाषण देते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात को रेखांकित किया था कि वेतनभोगी लोगों द्वारा दिया जाने वाला आयकर व्यक्तिगत कारोबारी करदाताओं द्वारा चुकाए गए आयकर का करीब तीन गुना होता है।

चूंकि वेतनभोगी वर्ग नियमानुसार अपने वेतन पर आयकर चुकाता है और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। ऐसे में, वेतनभोगी वर्ग के लाखों आयकरदाता यह कहते दिखाई देते हैं कि वे तो अपनी आमदनी पर ईमानदारी से आयकर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों पर भी सख्ती जरूर की जानी चाहिए, जो अच्छी कमाई के बाद भी टैक्स नहीं दे रहे या फिर हेराफेरी करके कम टैक्स दे रहे हैं। यदि सरकार उपयुक्त रूप से करदाताओं की संख्या बढ़ाएगी, तो इसका लाभ अधिक कर बोझ का सामना कर रहे ईमानदार करदाताओं को अवश्य मिल पाएगा। इससे ईमानदार करदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी।

कर क्षेत्र में ईमानदारी बढ़ाने के लिए सरकार को संबंधित व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। आयकर विभाग के ऑनलाइन सिस्टम को बहुत सरल व मजबूत बनाना होगा। हर स्तर पर ईमानदार करदाताओं को कर चुकाने में सुविधा देने के साथ-साथ सम्मान भी देना होगा। टैक्स सरलीकरण से भी ईमानदारी बढ़ेगी। जहां देश के ईमानदार करदाता लाभान्वित होंगे, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था भी गतिशील होगी। हम उम्मीद करें कि जब सरकार प्रत्यक्ष कर सरलीकरण की डगर पर आगे बढ़ रही है, तब यदि लोग ईमानदारी से कर चुकाते हुए न दिखाई दें, तो सरकार टैक्स वसूली की अपील से ज्यादा टैक्स वसूली की सख्ती की डगर पर आगे बढ़ेगी। निस्संदेह, ऐसा किए जाने से ईमानदार करदाताओं को कर के अधिक बोझ से बचाया जा सकेगा और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक धन जुटाया जा सकेगा।

उम्मीद है कि सरकार एक ऐसी महत्वाकांक्षी नई नीति तैयार करेगी, जिसके तहत लगातार ईमानदारी से पूरा कर और ऋण चुकाने वालों को 'सम्मानित' व प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी नीति से पूरे देश में यही संदेश जाएगा कि अब ईमानदार करदाताओं का उपहास नहीं होगा, उन्हें अपनी ईमानदारी के लिए पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें सम्मान मिलेगा और हार्दिक संतोष भी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जानलेवा प्रदूषण

प्रकृति के सम्मान में ही संकट का समाधान

रोहित कौशिक

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हर साल अक्तूबर-नवम्बर में दिल्ली-एनसीआर तथा देश के कई भागों में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। इस साल भी यही हाल है और विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिनों में हवा में प्रदूषण बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस प्रदूषण के लिए किसानों द्वारा पराली जलाने को एक बड़ा कारण माना जाता है लेकिन वास्तविकता यह है कि पराली जलाना इस समस्या का एक कारण है। कुछ लोग पराली जलाने की प्रक्रिया को ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे इस प्रदूषण का केवल यही एक कारण है। केवल पराली जलाने की प्रक्रिया को ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। इसके साथ अनेक कारण हैं जो इन दिनों प्रदूषण बढ़ाकर हवा की गुणवत्ता खराब करते हैं। हालांकि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार इस साल पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले करीब चार गुना अधिक दर्ज की गई हैं।

दरअसल तापमान कम होने और हवा की गति कम होने के कारण हवा के प्रदूषणकारी तत्व आसमान में ठहरे हुए हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी शरू हो गई है। दिल्ली सरकार हवा के प्रदूषण के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर पराली गलाने के लिए बायो डी कंपोजर का छिड़काव भी कराया जा रहा है। इसके माध्यम से पराली कुछ दिनों बाद खाद में तबदील हो जाती है।

दरअसल वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस के रोगियों की समस्या बढ़ जाती है और स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस सम्बन्धी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण के बढ़ने से कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इस समय हवा की गुणवत्ता पिछले आठ महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्रवाई की अपील की है।

हालांकि केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार के दावों को गलत बता रही है और इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। इसके कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों के अनुसार सरकार ने काम क्यों नहीं किया? दरअसल वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकारें जरूर सक्रिय होती हैं लेकिन जैसे ही प्रदूषण कम होता है, सरकारें पुनः सो जाती हैं जबकि वायु प्रदूषण कम करने वाले उपायों पर पूरे साल सक्रियता के साथ काम होते रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कोई भी तकनीक प्रदूषण को कम करने में सहायता तो कर सकती है लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती।

कई बार मौसम में परिवर्तन भी इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। रही-सही कसर हमारी नासमझी और मानवीय गतिविधियां पूरी कर देती हैं। यही कारण है कि सरकारी नीतियों के सही ढंग से क्रियान्वयन के साथ जब तक जनता पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी, वायु प्रदूषण को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता।

दरअसल धूल, धुएं और कुहासे से बना स्मॉग हमारे लिए कई समस्याएं पैदा करता है। जब ईंधन जलता है, वायुमंडलीय प्रदूषण या गैसें हवा में मौजूद सूरज की रोशनी और वातावरण में इसकी गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे स्मॉग बनता है। इस मौसम में हर साल इस स्मॉग के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। निमार्ण कार्य भी इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही वाहनों का प्रदूषण भी इस स्मॉग को बढ़ाता है। वाहनों से निकलने वाला इथाइलीन जैसा हाइड्रोकार्बन थोड़ी मात्रा में भी पौधों के लिए हानिकारक है। वास्तविकता यह है कि आज पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। पुराने जमाने में पर्यावरण के हर अवयव को भगवान का दर्जा दिया जाता था। इसीलिए हम पर्यावरण के हर अवयव की इज्जत करना जानते थे। नये जमाने में पर्यावरण के अवयव वस्तु के तौर पर देखे जाने लगे और हम इन्हें मात्र भोग की वस्तु मानने लगे। यह समझ विकसित करने के लिए एक बार फिर हमें नये सिरे से सोचना होगा।

हमें मानना होगा कि प्रदूषण की यह समस्या किसी एक शहर, राज्य या देश के सुधरने से हल होने वाली नहीं है। इस समय सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण के प्रति चिन्ता देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या खोखले आदर्शवाद से वायु प्रदूषण का मुद्दा हल हो सकता है? दरअसल जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से तो हमें हानि पहुंचाती ही है, परोक्ष रूप से भी हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी करती है। इस सम्बन्ध में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई सार्थक और ठोस हल नहीं निकल पाएगा।

छोटे किसान

इनके योगदान की समझ जरूरी

भारत डोगरा

देश व दुनिया दोनों स्तरों पर छोटे किसानों की खाद्य उत्पादन व कृषि विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

पर अनेक अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनकी बहुमूल्य भूमिका की उपेक्षा की जाती है व इसके स्थान पर महंगी मशीनों, महंगी तकनीकों के उपयोग वाली खेती की पैरवी की जाती है। इन तत्वों की पहुंच अनेक देशों में नीति-निर्धारकों तक होती है व उनके द्वारा प्रसारित नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर छोटे किसानों का विस्थापन हो रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने नया भ्रम भी फैला दिया है कि विकास के लिए बहुत से छोटे किसानों को खेती से हटा कर भीड़ कम करनी चाहिए। यह बहुत भ्रामक व हानिकारक सोच है पर इसे धड़ल्ले से फैलाया जा रहा है। नतीजातन अनेक देशों में छोटे किसानों के हितों के विरुद्ध नीतियां खुलेआम अपनाई जा रही हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति काल के बारे में अनुमान लगाया गया था कि प्रति 8 मिनट एक किसान परिवार (फैमली फार्म) का विस्थापन हुआ व इसे विकास का ढोल बजाते हुए मान्यता भी दिलवाई गई। सबसे अधिक दुख तो तब होता है जब ऐसी ही सोच भारत जैसे देशों में भी फैलाई जाती हैं, जहां मूलतः छोटे व मध्य किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना योगदान बनाए रखा। छोटे किसानों के विरुद्ध प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि उनकी उत्पादकता कम होती है। पर हकीकत यह है कि जब भली-भांति आकलन किया गया है तो प्रायः छोटे किसानों के खेतों पर उत्पादकता ज्यादा पाई गई है।

इसकी एक बड़ी बजह यह है कि प्रायः छोटे किसान मुख्य फसल के साथ अन्य खाद्य भी छोटे स्तर पर उगा लेते हैं व आकलन भी इन विविध छोटे स्तर पर उगाए गए खाद्यों का आकलन नहीं होता है। कभी मेढ़ पर तो कभी बेलों पर या कभी मुख्य फ़सल के बीच छोटे किसान अन्य उपयोगी खाद्य या अन्य उपज भी साथ-साथ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर बड़े फार्मो के मशीनीकृत तौर-तरीकों में प्रायः एक ही फसल बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है ताकि मशीनें अपने विभिन्न कार्य भली-भांति कर सकें। इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि एक ही फ़सल के बड़े क्षेत्र में फैले रहने के कारण उस फसल पर क्षति करने वाले कीड़ों, बीमारियों आदि का प्रकोप होता है। दूसरी ओर छोटे किसानों में मिश्रित खेती की कहीं अधिक क्षमता है व विभिन्न क्यारियों में, खेत के विभिन्न भागों में एक-दूसरे के अनुकूल विविध फ़सल उगा सकते हैं, जिससे कीड़ों व बीमारियों के प्रकोप की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। एक छोटे क्षेत्र में विविध तरह की फ़सल, फल-फूलों से विविध तरह के कीट व जंतु आते हैं, जो एक-दूसरे को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इससे मिली-जुली

छोटे किसान का अति महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक भूमिका यह भी रही है कि छोटे किसानों ने कृषि भूमि के प्राकृतिक उपजाऊपन को बचाए रखना का कार्य किया है। मानव इतिहास में छोटा किसान धरती मां की रक्षा, मिट्टी की रक्षा के सतत् प्रयासों के लिए ही पूजनीय रहा है। पर हाल के समय में बड़े फार्मो की अधिक मशीनीकृत खेती का प्रसार करने वाली कंपनियों के दबाव में विभिन्न सरकारों ने ऐसी नीतियां अपनाई, जिनसे छोटे किसानों की इस ऐतिहासिक भूमि को भी बहुत क्षति पंहुची है। दुष्प्रचार द्वारा उनसे भी ऐसी तकनीकें अपनाने के लिए दबाव डाला गया, जिससे मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊपन को क्षति पहुंची व किसान के मित्र-जीवों जैसे केंचुवों, मधुमक्खियों आदि को भी क्षति पंहुची।

इसके बावजूद आज भी छोटे किसान धरती के प्राकृतिक उपजाऊपन तथा स्वास्थ्य के अनुकूल खाद्यों के उत्पादन में बड़े मशीनीकृत फार्मो से कहीं अधिक सशक्त हैं। छोटे किसान ऐसी मिश्रित खेती कर सकते हैं, जो असंख्य सूक्ष्म जीवों व प्रकृति के लिए हितकारी है। किसान के मित्र केंचुवों व अन्य जीवों को छोटे किसान ही नया जीवन दे सकते हैं और पनपा सकते हैं। अतः यह सरकारी नीतियों का कर्तव्य है कि न केवल छोटे व मध्यम किसानों को सशक्त करें अपितु साथ में उन्हें अपनी उन प्रकृति व धरती की रक्षा की उस भूमिकाओं को निभाने के लिए भी प्रेरित व प्रोत्साहित करें जिन्होंने मानव इतिहास में छोटे किसान को पूजनीय बनाया है। बड़े फार्मो की मशीनीकृति खेती बहुत फासिल फ्यूल (जीवाम ईधन) मांगती है, जिससे ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जबकि छोटे किसान ऐसी खेती करने में कहीं अधिक सक्षम हैं जो एक ओर ग्रीनहाऊस गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन करती है व दूसरी ओर इन्हें मिट्टी में सोख कर इनका प्रदूषणकारी असर करने में भी अधिक सक्षम है।

बजाज फाइनेंस का दूसरी तिमाही मुनाफा 36 प्रतिशत गिरकर 965 करोड़ रुपये रहा

नयी दिल्ली, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 36 प्रतिशत घटकर 965 करोड़ रुपये रह गया। गैर- बैंकिंग क्षेत्र की इस वित्त कंपनी ने एक साल पहले इसी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 1,506 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में उसकी एकीकृत आय 3 प्रतिशत बढ़कर 6,523 करोड़ रुपये हो गई जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 6,323 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है। आलोच्य तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध ब्याज आय चार प्रतिशत बढ़कर 4,165 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो कि एक साल पहले 4,000 करोड़ रुपये रही थी। पुणे मुख्यालय वाली कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी बुक की गई कर्ज राशि 44 प्रतिशत घटकर 36.2 लाख रुपये रह गई जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 64.7 लाख रुपये रही थी। कंपनी की 30 सितबर 2020 को प्रबंधन के तहत रहने वाली कुल एकीकृत संपत्ति एक प्रतिशत बढ़कर 1,37,090 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले दूसरी तिमाही में यह 1,35,533 करोड़ रुपये रही थी। एकल आधार पर प्रबंधनाधीन संपत्ति 1,04,986 करोड़ रुपये रही जो कि 30 सितंबर 2019 को 1,10,946 करोड़ रुपये रही थी।

इनवर्टेड बैटरी ने शुरू की वारंटी समाप्त होने के बाद ई-रिक्शा बैटरी खरीदने की योजना

नयी दिल्ली. लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इनवर्टेड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने ई-रिक्शा बैटरियों की वारंटी समाप्त हो जाने के बाद उन्हें वापस करने पर 10 हजार रुपये देने की योजना शुरू की है। कंपनी ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि योजना 20 अक्टूबर से शुरू की गयी है। यह तिपहिया वाहन की लिथियम आयन बैटरी खरीदने की भारत की पहली योजना है। कंपनी के सह संस्थापक राघव जैन ने कहा, ''वारंटी अवधि समाप्त हो जाने के बाद इनवर्टेड ने बैटरी खरीदने की यह योजना शुरू की है, ताकि तेजी से लोग पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के माध्यमों को अपना सकें।''

सरकार 30.67 लाख कर्मचारियों को देगी 3,737 करोड़ रुपये का बोनस

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को 30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिये उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से संबद्ध बोनस देने का फैसला किया गया। बैठक में किये गये फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।'' कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है, ''गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है। सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।'' बयान के अनुसार, '' उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।'' इसमें कहा गया है, ''गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है।

मोरटोरियम पीरियड में ब्याज पर ब्याज माफ कर सकती है सरकार: सूत्र

बिजनेस डेस्क:

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला किया जिससे इस बार लोन लेने वालों की दिवाली अच्छी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने यह फैसला किया कि मोरटोरियम पीरियड के दौरान EMI पर लगने वाला ब्याज सरकार चुकाएगी। सूत्रों ने बताया कि अभी यह मामला कोर्ट में है तो सरकार इसकी जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी।

आम लोगों को यह ब्याज नहीं देना होगा

इस प्रस्ताव के मुताबिक, केंद्र सरकार EMI पर लगने वाला ब्याज अपनी तरफ से देगी। आम लोगों को यह ब्याज नहीं देना होगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार की यह स्कीम सिर्फ मोरटोरियम के 6 महीनों के दौरान ना चुकाए गए EMI के लिए हैं। कोरोनावायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ने इस साल 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक मोरटोरियम पीरियड लागू किया था। यानी इस दौरान अगर पैसों की किल्लत के कारण कोई EMI नहीं चुका पा रहा है तो उसका लोन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि इस दौरान ना चुकाए गए EMI पर बैंक ने ग्राहकों से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। जिसके खिलाफ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि MSME और इंडिविजुअल सेगमेंट को मिलाकर वह सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का कपाउंड इंटरेस्ट (EMI पर लगने वाला ब्याज) चुकाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। अब सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। हालांकि सरकार जब इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगी तब पता चलेगा कि सरकार किस हद तक ब्याज माफ करने वाली है। जस्टिस अशोक भूषण, आर एस रेड्डी और एमआर शाह ने सरकार को कहा था कि वह इस मामले में तेजी लाए।

एयरएशिया इंडिया ने छह नए घरेलू मार्ग पर शुरू की उड़ानें

मुंबई. निजी क्षेत्र की एयरएशिया इंडिया ने छह नए घरेलू हवाई मार्गों पर बुधवार से उड़ानें शुरू की। इसमें चेन्नई से अहमदाबाद एवं गोवा, मुंबई से विशाखापत्तनम एवं गोवा और जयपुर से कोलकाता की उड़ानें शामिल हैं। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इन मार्ग पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी ने कहा कि त्यौहारी मौसम में मांग बढ़ने के अनुमान को देखते हुए कंपनी ने देश में हवाई संपर्क बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत यह किया है। हवाई यातायात उद्योग के धीरे-धीरे पटरी पर लौटने के साथ ही कंपनी भी सतत गति से बढ़ रही है। एयरएशिया इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी अंकुर गर्ग ने कहा, '' त्यौहारी मौसम में यात्रियों की मांग में वृद्धि होने का अनुमान है। इन छह नए मार्गों के साथ हम देशभर में अपने नेटवर्क को मजबूत करते रहेंगे।''

मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में चालू सत्र के दौरान 12 लाख टन सेब खरीद को मंजूरी दी

नयी दिल्ली,

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता संस्था नाफेड को चालू सत्र में जम्मू-कश्मीर में 12 लाख टन सेब की खरीद के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को इस के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। सेब के काम में नाफेड को कोई नुकसान हुआ तो उसे केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन बराबर बराबर वहन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी बयान में कहा गया, ''केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू सत्र में भी बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत जम्मू-कश्मीर में सेब की खरीद को भी मंजूरी दी है जैसा कि पिछले सत्र 2019-20 के दौरान किया गया था।'' बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों से लगभग 12 लाख टन सेब खरीदा जा सकता है, और भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बयान के अनुसार, इससे सेब उत्पादकों को माल बेचने की एक अच्छी सुविधा होगी तथा वहां लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे सरकार का कहना है कि इस योजना से वहां उत्पादकों को सेब के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में किसानों की कुल आय में वृद्धि होगी।

विरल आचार्य ने केंद्र सरकार को चेताया, अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकती है यह अनदेखी

बिजनेस डेस्क:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार बैंको के पूंजीकरण की अनदेखी कर रही है और इसमें हुई देरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकती है। विरल आचार्य ने कहा कि सरकार का फोकस अभी केवल मोरेटोरियम और कर्जदारों की Interest माफी पर है और वह बैंको में पूंजी डालने में देरी कर रही है।

मार्च तक दोगुना होगा NPA

विरल आचार्या ने कहा कि RBI के अनुमान के मुताबित, देश के बैंक अभी 120 बिलियन डॉलर यानी 8,80,041 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं और मार्च तक इसकी राशि यानी एनपीए (NPA) दोगुनी होने की आशंका है। इससे बैंक काफी दिक्कत में हैं। उन्होंने कहा था कि यह बहुत जरूरी है कि सरकार बैंकों को पैसा दे।

सरकार पर साधा निशाना

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विरल आचार्य ने कहा कि बैंकों को रिकवरी के लिए पैसों की जरूरत है लेकिन सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह अनदेखी शॉर्ट टर्म में लाभ के लिए वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इससे लोग सड़क पर आ सकते हैं और देश वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर सकता है।

बार-बार की गलतियों ने भारत का विकास रोका

आचार्य ने कहा कि बार-बार की गई इस गलती ने भारत को विपरीत झटकों से अच्छी तरह उबरने से रोक दिया है। उनकी यह टिप्पणी भारत द्वारा छह महीने तक कर्ज के मोरेटोरियम की शर्तों को कानूनी चुनौती के बाद 2 करोड़ रुपए तक के सभी लोन पर ब्याज को माफ करने के ऑफर के कुछ हफ्तों बाद आई है। विरल आचार्य ने कहा कि शॉर्ट टर्म में कर्जदारों को लोन मोरेटोरियम और Interest waiver देना मीडियम टर्म में क्रेडिट ग्रोथ की रिकवरी रोक सकती है। उन्होंने कहा कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) पैकेज में यह सुनिश्चित करने के लिए ठीक-ठाक उपाय किए गए हैं, ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो सके।

पिछली गलतियों से सबक सीखने का समय

विरल आचार्य ने कहा कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग से होने वाले नुकसान के लिए एक अलग फंड बनाया जाना चाहिए ताकि महामारी से निकलने के बाद देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने पर विकास की गति नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर सरकार समय से बैंकों का पूंजीकरण (bank recapitalisation) नहीं करना चहती है तो लोन मोरेटोरियम और माफी जैसी योजनाओं के लिए बैंक पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। लोन मोरेटोरियम और माफी जैसी योजनाओं से बैंकों को आगे कर्ज देने में और दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह पिछली गलतियों से सबक सीखने का समय है।

बिजली बिक्री दूसरी तिमाही में 13.2% बढ़ी: आईईएक्स

नई दिल्ली:

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने बुधवार को कहा कि सितंबर तिमाही में उसकी बिजली बिक्री 13.2 प्रतिशत बढ़कर 1648.6 करोड़ यूनिट रही। बिजली मांग बढ़ने और कोविड-19 के पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ एक्सचेंज में बिक्री बढ़ी है। आईईएक्स ने एक बयान में कहा कि दूसरी तिमाही में औद्योगिक गतिविधियों और बिजली खपत में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका कारण देश भर में 'लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में ढील दिया जाना है। बयान के अनुसार एक्सचेंज में बिजली बिक्री चालू वित्त वर्ष 220-21 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13.2 प्रतिशत बढ़कर 1648.6 करोड़ यूनिट रही। जबकि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में यह 1,456.0 करोड़ यूनिट थी। दूसरी तिमाही में शुरू में विनिर्माण गतिविधियां धीमी रही। इसका कारण कुछ राज्यों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दोबारा से 'लॉकाउन लगाया जाना था। हालांकि अगस्त और सितंबर में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई। आईईएक्स ने कहा कि आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग भी बढ़ी और कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच गई। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत और खपत में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

त्योहारी सीजन में SBI का शानदार ऑफर, होम लोन की ब्याज दरों में की कटौती

मुंबई:

त्योहारी सीजन में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को होम लोन पर ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के हिसाब से 'योनो% के जरिए आवेदन करने पर 75 लाख रुपए से अधिक के होम लोन पर ब्याज में 0.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योनो बैंक का डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है।

एसबीआई की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अपनी त्योहारी पेशकश के तहत वह ग्राहकों को 30 लाख रुपए से अधिक के और दो करोड़ रुपए तक के आवास ऋण पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की छूट देगा। पहले बैंक ने 0.10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की थी। यह योजना देशभर के लिए होगी। यही छूट आठ महानगरों में तीन करोड़ रुपए तक के आवास ऋण पर दी जाएगी। यदि ग्राहक योनो मंच के जरिए ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। बैंक अभी 30 लाख रुपए तक का होम लोन 6.90 प्रतिशत की निचली ब्याज दर पर दे रहा है। 30 लाख रुपए से अधिक के होम लोन पर ब्याज दर सात प्रतिशत है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक (खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग) सी एस शेट्टी ने कहा, ''एसबीआई के सस्ते आवास ऋण के जरिए घर खरीदार अपने सपनों का आशियाना खरीद सकेंगे। अब देश कोविड-19 के बाद के दौर के लिए तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता मांग अब सुधर रही है। एसबीआई में हम ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप आकर्षक पेशकश लाते रहेंगे। पिछले महीने बैंक ने अपने खुदरा ऋण ग्राहकों के लिए कई त्योहारी पहल की थीं। इसके तहत योनो के जरिए कार, सोने या व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग शुल्क से छूट दी गई थी।

एसबीआई का बड़ा ऑफर

75 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए, सिबिल स्कोर के आधार पर ब्याज में 0.20 तक की छूट

आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद दरों में रियायत प्रदान करेगा बैंक

स्वद्ध योनो ऐप के माध्यम से आवेदन करने पर सभी प्रकार के होम लोन पर अतिरिक्त 0.05 फीसदी की छूट

30 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक के लोन के लिए ग्राहकों को मिलेगी 0.10 फीसदी तक क्रेडिट स्कोर आधारित रियायत

घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए ब्याज में 0.05 फीसदी की अतिरिक्त रियायत

30 लाख रुपए तक के होम लोन के लिए सबसे कम ब्याज दर 6.90 फीसदी से शुरू

घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए पैसे तो क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?

बिजनेस डेस्क:

कोरोना काल में अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। हर छोटी-बड़ी चीज के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। यहां तक कि लोग घर की सब्जी और राशन भी या तो ऑनलाइन खरीद रहे हैं या फिर कम से कम उसका भुगतान तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब अगर घर का राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े कामों को जोड़ें तो हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा? ऐसा नहीं करने पर कहीं आयकर विभाग का नोटिस तो नहीं आ जाएगा? चलिए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन।

महीने के खर्च पर नहीं लगेगा टैक्स

अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा यानी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग का कोई नोटिस नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है और एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और टैक्स लगेगा।

पत्नी ने पैसे कहीं निवेश करें तो लगेगा टैक्स

अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल हो जाएगी यानी अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी। हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट का फायदा मिलेगा लेकिन उसे आईटीआर फाइल करना होगा।

पत्नी को दिए पैसे गिफ्ट माने जाते हैं

अगर आयकर कानून के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इस पर पति को भी किसी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी यानी पत्नी को टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही पति की टैक्स देनदारी बनी रहेगी और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।

सेबी प्रमुख का धन जुटाने के लिये वित्तीय क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम करने पर जोर

मुंबई

सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को कहा कि धन जुटाने के मामले में देश के वित्तीय क्षेत्र में विविधीकरण की जरूरत है और यह बदलाव पूंजी बाजार से धन जुटाने की तरफ झुका होना चाहिए। त्यागी ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''भारत में वर्तमान में वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से बैंक के कर्ज पर निर्भर है। इस स्थिति में विविधीकरण की जरूरत है खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र की समस्या को देखते हुये पूंजी बाजार के जरिये धन जुटाने में सहूलियत की जानी चाहिये।'' पूंजी बाजार नियामक ने चेतावनी देते हुये कहा कि जब तक बॉंड बाजार को समुचित रूप से विकसित नहीं किया जायेगा तब तक 2024- 25 तक अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश के सरकार के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इक्विटी बाजार तो काफी सक्रिय है लेकिन भारत कार्पोरेट बॉंड बाजार के विकास को लेकर पिछले कई सालों से मशक्कत कर रहा है।

त्यागी ने कहा कि जब तक देश में बॉंड बाजार को उपयुक्त ढंग से विकसित नहीं कर लिया जाता है 2024- 25 तक देश के अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि बॉंड बाजार के विकास के लिये ''गहरे ढांचागत और नियामकीय बदलावों'' की आवश्यकता होगी। इसके लिये सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। त्यागी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्पोरेट बॉंड बाजार को विकसित करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल बॉंड इक्विटी और रिण बाजार से कुल मिलाकर औसतन 9 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाते हैं।

वीडियोकॉन दिवाला मामला: धूत परिवार ने ऋणदाताओ को 30,000 करोड़ रुपये की पेशकश की

नई दिल्ली.

वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए धूत परिवार ने ऋणदाताओं को 30,000 करोड़ रुपये अदा करने की पेशकश की है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के निलंबित बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल धूत ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ऋणदाताओं के बकाया कर्ज को चुकाने का प्रस्ताव ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) को भेजा गया है। दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने के बाद कंपनी के बोर्ड को निलंबित कर दिया गया था। समूह के पूर्ववर्ती प्रवर्तक धूत परिवार को उम्मीद है कि समाधान पेशकश पर अंतिम फैसला इस साल के अंत तक आ जाएगा।

इसके लिए जरूरी है कि ऋणदाता और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) इसपर सहमति हों। वीडियोकॉन समूह की सीआईआरपी के तहत कुल 15 कंपनियां हैं। इनमें से 13 कंपनियों के लिए यह समाधान या निपटान पेशकश की गई है। समूह की दो कंपनियां केएआईएल और ट्रेंड इस पेशकश में शामिल नहीं हैं। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने समाधान की प्रक्रिया को तेज करने और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समूह की 15 कंपनियों को एक साथ 'मिला' दिया था। धूत ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इसपर अंतिम फैसला अगले 30 से 60 दिन में आ जाएगा।' आईबीसी की धारा 12ए के तहत न्यायाधिकरण कुछ शर्तों के साथ किसी कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। संबंधित समाधान पेशवर को दिवाला प्रक्रिया को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाना होगा। सीओसी के मताधिकार वाले 90 सदस्यों की प्रस्ताव पर मंजूरी जरूरी होती है। धूत ने कहा कि धारा 12ए के तहत ताजा प्रस्ताव अक्टूबर, 2017 में किए गए इसी तरह के प्रस्ताव की तरह है। इस प्रस्ताव को संयुक्त ऋणदाता मंच ने मंजूर कर भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया था। उन्होंने कहा, 'अक्टूबर, 2017 के मूल प्रस्ताव के तहत ऐसा ऋण जिसके पुनर्गठन पर विचार होना था, 31,289 करोड़ रुपये था। इसमें कुल बकाया ऋण में कर्जदारों को कछ नहीं छोड़ना पड़ेगा।'

मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना अब होगा महंगा, 500 रुपए तक स्पेशल फीस की तैयारी

बिजनेस डेस्क:

कोरोना महामारी के कारण एविएशन सेक्टर का हाल बहुत खराब है। भारत में डोमेस्टिक एयर सर्विस शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी तक शेड्यूल इंटरनैशनल फ्लाइट की सेवा शुरू नहीं हुई है। कमाई घटने के कारण मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी (MIAL) ने यात्रियों से यूजर्स डिवेलपमेंट फीस (UDF) वसूलने का फैसला किया है। यह आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा।

ऑपरेशनल खर्च मुश्किल से निकल पा रहा

कोरोना महामारी के बीच एयर ट्रैफिक कम होने के कारण मुंबई एयरपोर्ट का ऑपरेशनल खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में MIAL ने हर यात्री से 200-500 रुपए वसूलने का फैसला किया है। पहले डमेस्टिक पैसेंजर्स से कोई यूडीएफ नहीं वसूली जाती थी, जबकि इंटरनैशनल पैसेंजर्स से 116 रुपए वसूली जाती थी।

500 रुपए तक फीस

मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए ऐडहॉक फीस 200 रुपए का ऐलान किया है। पहले यह शून्य थी।

इंटरनैशनल पैसेंजर्स के लिए यह 500 रुपए होगी। पहले से यह चार्ज 116 रुपए था जो अब बढ़कर 616 रुपए हो गया। विदेशी करंसी में इंटरनैशनल टिकट बुक करने वालों से 7.23 डॉलर यूजर्स डिवेलपमेंट फीस वसूली जाएगी। पहले यह 1.68 डॉलर थी। कुल मिलाकर अब यह 8.91 डॉलर हो गई।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एफसी बार्सिलोना ने पिके, स्टेगेन, जोंग और लेंगलेट के करार बढ़ाए

बार्सिलोना। स्पेनिश लीग क्लब एफसी बार्सिलोना ने गेरार्ड पिके, मार्क टेर स्टेगेन, फ्रेंकी दे जोंगे और क्लेमेंट लेंगलेट के करार बढ़ा दिए हैं। पिके अब क्लब के साथ 2024 तक बने रहेंगे और उनका बाई आउट क्लाउस 50 करोड़ यूरो में मान्य होगा। पिके का यह क्लब के साथ 13वां सीजन है और वह क्लब के लिए 548 मैच खेल चुके हैं। इसी तरह स्टेगेन 2025 तक क्लब के साथ रहेंगे। उनका भी बाई आउट क्लाउज 50 करोड़ यूरो का होगा। जर्मन गोलकीपर अब त क्लब के लिए 236 मैच खेल चुके हैं। क्लब ने कहा है कि जोंग 2026 तक क्लब को सेवाएं देते रहेंगे और लेंगलेट भी 2026 तक ही टीम में रहेंगे। जोंग ने बार्का के लिए 47 मैच खेले हैं जबकि लेंगलेट 89 मैच खेल चुके हैं।

राजस्थान, हैदराबाद की भिड़ंत गुरुवार को, प्लेऑफ के लिए अहम है यह मैच

दुबई।

राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन के अपने पिछले मैच में तीन बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार तरीके से मात दी थी। इस जीत में राजस्थान के लिए एक अच्छी बात यह रही थी कि टीम ने सभी विभागों में अच्छा किया था। अब उसे गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करना है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच पहला मैच खेला गया था, जहां राहुल तेवतिया और रियान पराग ने मिलकर राजस्थान को हार के रास्ते से बाहर निकाल जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर राजस्थान अपने पुराने प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगी। पिछले मैच में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उससे वह आत्मविश्वास से लबरेज होगी। गेंदबाजी में खासकर, क्योंकि टीम ने चन्नई को बड़ा स्कोर खड़ा करने नहीं दिया था। चेन्नई 20 ओवरों में सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। जोफा आर्चर, कार्तिक त्यागी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार श्रेयस गोपाल और तेवतिया रहे थे। गोपाल ने चार ओवरों में 14 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था जबकि तेवतिया ने चार ओवरों में 18 रन ही खर्च किए और एक विकेट लिया था। हैदराबाद के खिलाफ टीम इन दोनों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आईपीएल में अब स्पिनरों के हिसाब की पिचें देखी जा सकती हैं और इसलिए राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए गोपाल-तेवतिया की जोड़ी एक बड़ा हथियार होगी। वहीं बल्लेबाजी में जोस बटलर को मध्य क्रम में लाना टीम के लिए पिछले मैच में तो काम कर गया था। बटलर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। स्मिथ ने भी उनका बखूबी साथ दिया था। रॉबिन उथप्पा और संजू सैमसन विफल रहे थे। बेन स्टोक्स भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। बतौर सलामी बल्लेबाज उथप्पा खतरनाक बल्लेबाज हैं और टीम उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करती है तो यह टीम और उथप्पा दोनों के लिए अच्छा होगा। बीते दो मैचों में तो टीम ने उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही भेजा है और उम्मीद की जा सकती है कि यह क्रम लीग के आने वाले मैचों में भी जारी रहेगा। बेन स्टोक्स से हालांकि अभी तक बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। स्टोक्स खुद भी बड़ी पारी खेलने को लेकर उत्सुक होंगे। संजू सैमसन को अपनी फॉर्म में लौटना होगा। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनपर टीम काफी हद तक टिकी हुई है और वह टीम की बल्लेबाजी की अहम कड़ी हैं।

आईएसएल : ईस्ट बंगाल की 22 सदस्यीय टीम में जेजे और बलवंत शामिल

पणजी।

एससी ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सीजन के लिए अपनी 22 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में भारतीय फारवर्ड जेजे लापपेखलुआ के अलावा अनुभवी फारवर्ड बलवंत सिंह, नारायण दास, इग्युनसेन लिंगदोह और मोहम्मद रफीक जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। 33 साल के बलवंत ने दो सीजन एटीके के साथ बिताए हैं और क्लब के लिए वह अब तक कुल 23 मुकाबले खेल चुके हैं। बलवंत ने कहा कि ईस्ट बंगाल का नाम ही प्रेरित करने के लिए काफी है और वह अपनी तथा टीम की साख के साथ पूरा न्याय करने का प्रयास करेंगे। नारायण ने बीते सीजन में ओडिशा एफसी के लिए

18 मैच खेले थे। अंतिम बार वह भारत के लिए एशियन कप में खेले थे। इसी तरह 34 साल के लिंगदोह ने एटीके के लिए खेलने के बाद ईस्ट बंगाल का रुख किया है। बीते सीजन में वह चोट के कारण अधिकांश समय बेंच पर ही रहे थे।

ईस्ट बंगाल टीम :

भारतीय दस्तः

गोलकीपरः शंकर रॉय, देबजीत मजुमदार, मो. रफीक अली सरदार, मिरशद कोटापुन्ना

डिफेंडरः गुरतेज सिंह, नारायण दास, समद अली मल्लिक, लालराम चुल्लोवा, मोहम्मद इरशाद, एन रोहन सिंह, अभिषेक अम्बेकर, राणा घरामी

मिडफील्डर्स : सेहनाज सिंह, बिकास जायरू, यूजीनसन लिंगदोह, युमनाम गोपी सिंह, वाहेंगबम अंगसाना, मो. रफीक, मोइरंगथेम लोकेन मेइत्ती, सुरचंद्र सिंह चंदम।

फॉरवर्डः जीजे लालपेखलुआ, बलवंत सिंह।

आईएसएल : मुम्बई सिटी एफसी ने ओग्बेचे से करार किया

मुम्बई। मुम्बई सिटी एफसी ने बुधवार को स्ट्राइकर बार्थोलोमेव ओग्बेचे के साथ करार करने की घोषणा की। मुम्बई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सीजन के लिए ओग्बेचे को अपने साथ जोड़ा है। क्लब ने कहा है कि यह करार एक साल के लिए होगा। ओग्बेचे ने इस करार को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि मुम्बई सिटी एफसी में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है और इस टीम में खिताब जीतने की इच्छा भी है। मैं इस टीम के लिए अपना सौ फीसदी देने का प्रयास करूंगा। 36 साल के ओग्बेचे आईएसएल में नार्थईस्ट युनाइटेड एफसी और केरला ब्लास्टर्स के लिए खेल चुके हैं। दोनों टीमों की उन्होंने कप्तानी की थी। नार्थईस्ट के लिए ओग्बेचे ने 18 मैचों में 12 और ब्लास्टर्स के लिए 16 मैचों में 15 गोल किए थे।

ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना एकमात्र लक्ष्य : दिलप्रीत

बेंगलुरु ।

भारतीय हॉकी पुरुष टीम के फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह का कहना है कि खेलो के महाकुंभ ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। अब तक के अपने छोटे करियर में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ब्रेडा 2018 में रजत पदक और एशियाई खेलों 2018 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में शामिल रहे दिलप्रीत ने कहा कि वर्तमान चरण भारतीय टीम में युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने कहा- कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक के वर्ष 2021 तक स्थगित होने से उभरते हुए युवा खिलाडियों के पास अपने कौशल और प्रतिभा को निखार कर ओलंपिक टीम में जगह बनाने का बड़ा मौका है। दिलप्रीत ने कहा- ओलंपिक तक पहुंचने वाले महीने युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण होते हैं क्योंकि इस तरह के अवसर रोज़ नहीं आते हैं। ओलंपिक में खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना है और हम सभी के पास कुछ ही महीनों में अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का एक बड़ा मौका है।

फॉरवर्ड खिलाड़ी ने कहा- मैदान पर फिर से वापसी करना निश्चित रूप से अछूत है। मुझे खेल के लिए अपने आप में एक नया जोश मिला है और मैं इसके हर मिनट से प्यार कर रहा हूं। हम इस हम समय ले रहे है लेकिन हम हर दिन सुधार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीनों में हॉकी इंडिया और साई असाधारण रूप से मददगार रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

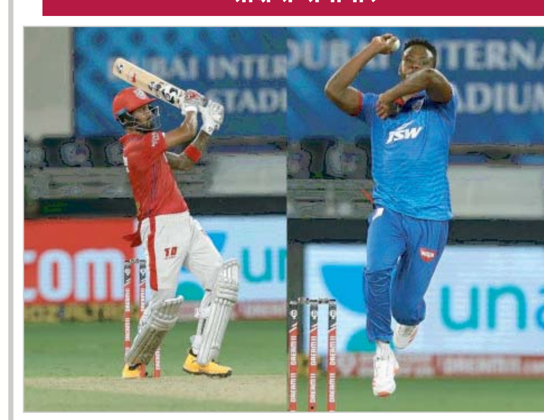

आईपीएल-13 : ऑरेंज कैप राहुल, पर्पल रबाडा के पास बरकरार

दुबई। आईपीएल-13 के 38 मैचों की समाप्ति के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने ऑरेंज कैप अपने पास ही रखी है।राहुल के 10 मैचों में 540 रन हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन हैं, जिनके नाम 10 मैचों से 465 रन हैं। धवन ने आईपीएल में लगातार दो शतक लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। पंजाब के ही मयंक अग्रवाल 465 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में दिल्ली के कगिसो रबाडा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर हैं। 10 मैचों में रबादा ने 21 विकेट लिए हैं। उनके बाद पंजाब के मोहम्मद शमी का नाम है, जिनके नाम 16 विकेट हैं। मुम्बई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह के नाम 15 विकेट हैं और वह तीसरे क्रम पर हैं।

ग्रोइन इंजुरी के कारण आईपीएल 13 से बाहर हुए ब्रावो

दुबई। खराब दौर से गुजर रही चेन्नई सुपर किंग्स को बुधवार को उस समय करारा झटका लगा, जब उसके हरफनमनौला खिलाड़ी ड्वायन ब्रावो ग्रोइन इंजुरी के कारण आईपीएल के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए। सीएसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कासी विश्वनाथन ने बताया है कि ब्रावो को राइट ग्रोइन में ग्रेड-1 टीयर है और वह गुरुवार को अपने देश लौट जाएंगे। 37 साल के ब्रावो को दिल्ली कैपिटल्स के साथ 17 अक्टूबर को हुए मैच के दौरान चोट लगी थी। इस चोट के कारण वह सीएसके के लिए अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नहीं खेल सके थे। सीएसके वह मैच सात विकेट से हार गई थी। इस सीजन में ब्रावो ने सीएसके के लिए सिर्फ छह मैच खेले और सात रन बनाने के अलावा छह विकेट हासिल किए। सीएसके का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। इस टीम ने 10 मैचों से सिर्फ छह अंक जुटाए हैं और अभी आठ टीमों की तालिका में सबसे नीचे है। शारजाह में शुक्रवार को सीएसके का सामना मुम्बई इंडियंस से होना है।

यूरो 2020 की मेजबानी को लेकर अजरबैजान के लिए यूएफा से कोई खतरा नहीं

जेनेवा ।

यूरोपीय फुटबॉल महासंघों के संघ (यूएफा) ने कहा कि पड़ोसी देश अर्मीनिया से संघर्ष के बाद भी वह यूरोपीय चैम्पियनशिप के मैचों को अगले अजरबैजान की मेजबानी में कराने की योजना जारी रखेगा। यूएफा ने हालांकि कहा है कि 'अगली सूचना तक अजरबैजान किसी मैच की मेजबानी नहीं करेगा। बाकू (अजरबैजान) को जून में यूरो 2020 के ग्रुप चरण के तीन मैचों के अलावा तीन जुलाई को क्वार्टर फाइनल मुकाबले की मेजबानी करनी है। ग्रुप चरण के मैच स्विट्जरलैंड, तुर्की और वेल्स से जुड़े हुए है। इस 24 देशों के टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुने गये 12 देशों में से अजरबैजान एक है। टूर्नामेंट को हालांकि कोविड-19 के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। आर्मीनिया और आजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर हुए संघर्ष के बाद यूएफा ने नेशंस लीग के मैचों को तटस्थ देशों में स्थानांतरित कर दिया था। यूएफा से मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक कि यूईएफए का मानना है कि वर्तमान समय में इन देशों में मैचों के आयोजन के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। बयान के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों का हालांकि अगले साल जून में यूएफा यूरो2020 के मैचों को बाकू में कराने की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

गेल के दोनों पैर बांधकर गेंदबाजी करनी चाहिए : अश्विन

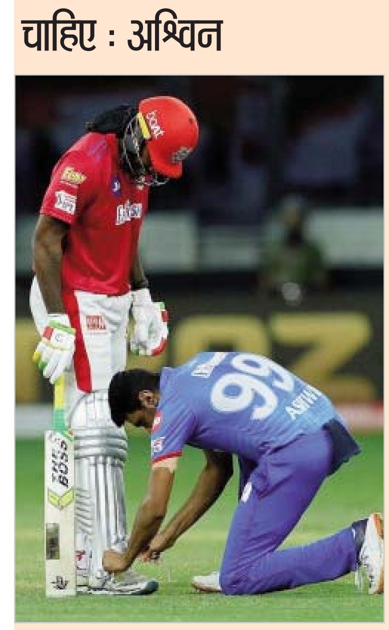

नई दिल्ली। किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल-13 मुकाबले में क्या हराया, खिलाड़ियों की भावनाएं सामने आने लगी हैं। इसी तरह की एक भावना दिल्ली के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने व्यक्त की है। मंगलवार को हुए मैच में अश्विन एक पल गेल के जूतों का फीता बांधते नजर आए थे। इस फोटो को अश्विन ने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि मैं तो गेल के जूतों के फीते बांध रहा था लेकिन ऐसे बल्लेबाज के दोनों पैर बांधकर उसे गेंदबाजी करनी चाहिए। अश्विन ने लिखा, गेल के तो दोनों पैर बांधकर गेंदबाजी करनी चाहिए। हमारे लिए कठिन दिन था लेकिन हम वापसी करेंगे। इस मैच में दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार नाबाद 106 रन बनाए। वह आईपीएल में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। धवन ने भी स्वीकार किया है कि यह उनकी टीम के लिए कठिन मैच था लेकिन इस मैच से काफी कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेगी। धवन इस मैच में शतक लगाने के साथ धवन ने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए थे। वह ऐसा करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इस जीत के बाद पंजाब की टीम आठ अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली के खाते में 14 अंक हैं और वह अभी भी टॉप पर है। यह मैच जीतने की स्थिति में दिल्ली की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर गई होती। इधर, पंजाब ने इस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।

ला लीगा ने फुटबाल फैन्स के लिए लॉन्च किया नया वर्ड गेम

मुम्बई । स्पेनिश फुटबाल लीग-ला लीगा ने फुटबाल फैन्स के लिए नया वर्ड गेम लॉन्च किया है। ला लीगा का नया ऑफिशियल गेम यूजर्स को मौज मस्ती के साथ चुनौतियों का सामना करने का मौका देगा।इसके अलावा ला लीगा ने मिनीगेम्स भी लॉन्च किए हैं, जिनमें वर्डप्ले के अलावा फुटबाल भी शामिल है। ऐप डेवलपर एपिक पांडा गेम्स द्वारा तैयार इन गेम्स के साथ ला लीगा मोबाइल गेम्स के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहले खेल संगठन बन गया है। ला लीगा का वर्ड गेम चार भाषाओं-स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और पुर्तगीज में उपलब्ध होगा।

मैच को 19वें ओवर में खत्म करना अच्छा था : राहुल

दुबई।

किंग्स इलेवन पंजाब ने मंगलवार रात को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात दे लगातार तीसरी जीत हासिल की। इन तीनों में पहले मैच में उसे आखिरी गेंद पर जीत मिली थी जबकि दूसरा मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो सुपर ओवर में गया था। दिल्ली के खिलाफ जरूर पंजाब ने 19वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने कहा है कि एक मैच में तो करीबी जीत से बचे रहना अच्छा है। पंजाब ने दिल्ली द्वारा रखे गए 165 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में ही हासिल कर लिया था। राहुल ने कहा, एक बार तो 19वें ओवर में जीत हासिल करना अच्छा है। राहुल और उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल इस मैच में जल्दी आउट हो गए थे और क्रिस गेल भी नहीं चले थे। टीम के मध्य क्रम ने पंजाब को जीत दिलाई। राहुल ने कहा कि उनके शीर्ष क्रम के लिए जरूरी है कि कोई न कोई अंत तक टिका रहे। उन्होंने कहा, जब आप छह बल्लेबाजों और एक हरफनमौला खिलाड़ी के साथ खेलते हो तो यह जरूरी है कि सेट बल्लेबाज, या शीर्ष चार में से एक अंत तक टिका रहे और मैच खत्म करे।राहुल ने अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ की है।

राहुल ने कहा कि शमी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए सुपर ओवर में गेंदबाजी करने से आत्मविश्वास मिल है । उन्होंने कहा, शमी को पिछले मैच से आत्मविश्वास मिला है, उन्होंने जिस तरह से सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी वो शानदार है। जैसा मैंने कहा, वह टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में दो ओवर गेंदबाजी की और फिर डेथ ओवरों में एक और ओवर फेंका। उन्होंने छह यॉर्कर गेंदें डालीं। यह तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं है। यह बताता है कि हमारे खिलाड़ियों ने किस तरह की मेहनत की है।

यूनिस, मुश्ताक को जिम्बाब्वे सीरीज के कोचिंग स्टाफ टीम में जगह मिलना मुश्किल

लाहौर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच यूनिस खान और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद को इस महीने के अंत में जिम्बाब्वे के साथ शुरू हो रही सीमित ओवरों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्टाफ टीम में शामिल किया जाना मुश्किल है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसीबी ने अब तक यूनिस के साथ करार में विस्तार नहीं किया है। पीसीबी मानता है कि खान टेस्ट टीम के लिए उपयुक्त बैटिंग कोच हैं लेकिन वनडे और टी20 फॉरमेट के लिए वह उपयुक्त नहीं हैं। यूनिस की गैरमौजूदगी में मुख्य कोच मिस्बाह उल हक को ही बैटिंग कोच की भूमिका निभानी पड़ सकती है। मौजूदा टीम स्टाफ में हक के अलावा टीम मैनेजर मंसूर राणा, गेंदबाजी कोच वकार यूनिस, फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद, फिजियो क्लिफ डेकरन, स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक, सिक्योरिटी मैनेजर कर्नर रिटायर्ड उस्मान, मीडिया मैनेजर रजा राशिद और मसाजर मलंद अली शामिल हैं। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। ये दोनों सीरीज 30 अक्टूबर से 10 नवम्बर के बीच खेली जानी हैं।

मुक्ता गिरी जैन सिद्ध क्षेत्र

जहां आज भी होती है केसर-चंदन की वर्षा

दिगंबर जैनियों का सिद्धक्षेत्र भारत के मध्य में, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित है मुक्ता गिरी। मुक्ता गिरी मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आता है। सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला में मन मोहनेवाले घने हरे-भरे वृक्षों के बीच यह क्षेत्र बसा हुआ है। जहां से साढ़े तीन करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। इसीलिए कहा जाता है -

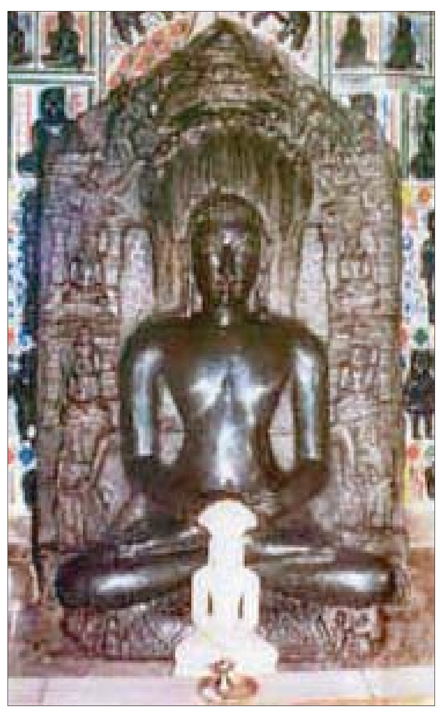

अचलापूर की दिशा ईशान तहां मेंढागिरी नाम प्रधान।

साढ़े तीन कोटी मुनीराय तिनके चरण नमु चितलाय।।

जहां 250 फुट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। जिससे जलप्रपात निर्मित हुआ है। निसर्ग के हरे-भरे उन दृश्यों एवं पहाड़ों को देखकर हर मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस स्थान को मुक्तागिरी के साथ-साथ मेंढागिरी भी कहा जाता है।

मुक्ता गिरी का इतिहास : एलिचपूर यानी अचलपुर में स्थित मुक्ता गिरी सिद्धक्षेत्र को स्व. दानवीर नत्थुसा पासुसा कळमकर ने अपने साथी स्व. रायसाहेब रूखबसंगई तथा स्व. गेंदालालजी हीरालालजी बड़जात्या के साथ मिलकर अंग्रेजों के जमाने में खापर्डे के मालगुजारी से सन् 1928 में यह मुक्तागिरी पहाड़ मंदिरों के साथ खरीदा था। इस मुक्ता गिरी सिद्धक्षेत्र का इतिहास काफी रोमहर्षक है।

कहा जाता है कि उस समय शिकार के लिए पहाड़ पर जूते-चप्पल पहन कर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह पहाड़ खरीदा गया।

निर्वाण कांड में उल्लेख है कि इस क्षेत्र पर दसवें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का समवशरण आया था। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ता गिरी पर मुक्ता बरसे। शीतलनाथ का डेरा। ऐसा उस वक्त मोतियों की वर्षा होने से इसे मुक्तागिरी कहा जाता है।

एक हजार वर्ष पूर्व मंदिर क्रमांक दस के पास ध्यान मग्न मुनिराज के सामने एक मेंढा पहाड़ की चोटी से गिरा। मुनिराज ने उसके कान में णमोकार मंत्र का उच्चारण किया। वह मेंढा मृत्यु के बाद स्वर्ग में देवगति प्राप्त होते ही मुनि महाराज के दर्शन को आया। तब से हर अष्टमी और चौदस को यहां केसर-चंदन की वर्षा होती है। इसी समय से इसे मेंढागिरी भी कहा जाता है।

जानिए धारकुंडी के सौंदर्य की महिमा

जहां पहाड़ों से बहती जल की धारा

कटनी-इलाहाबाद रेल मार्ग में सतना से 70 किलोमीटर दूर धारकुंडी में प्रकृति और अध्यात्म का अनुपम मिलन देखने को मिलता है। सतपुड़ा के पठार की विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित धारकुंडी में प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है।

पर्वत की कंदराओं में साधना स्थल, दुर्लभ शैल चित्र, पहाड़ों से अनवरत बहती जल की धारा, गहरी खाईयां और चारों ओर से घिरे घनघोर जंगल के बीच महाराज सच्चिदानंद जी के परमहंस आश्रम ने यहां पर्यटन और अध्यात्म को एक सूत्र में पिरो कर रख दिया है। यहां बहुमूल्य औषधियां और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। माना जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और दक्ष का प्रसिद्ध संवाद यहीं के एक कुंड में हुआ था जिसे अघमर्षण कुंड कहा जाता है। यह कुंड भूतल से करीब 100 मीटर नीचे है।

धारकुंडी मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। धार तथा कुंडी यानी जल की धारा और जलकुंड। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के दो पर्वत की संधियों से प्रस्फुटित होकर प्रवाहित होने वाली जल की निर्मल धारा यहां एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण करती है।

समुद्र तल से 1050 फुट ऊपर स्थित धारकुंडी में प्रकृति का स्वर्गिक सौंदर्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत उपलब्ध कराता है। यहां जनवरी में जहां न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री रहता है वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहता है। जून माह में न्यूनतम 20 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहता है।

योगिराज स्वामी परमानंद जी परमहंस जी के सान्निध्य में सच्चिदानंद जी ने चित्रकूट के अनुसूया आश्रम में करीब 11 वर्ष साधना की। इसके बाद सच्चिदानंद जी महाराज 1956 में यहां आए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को आश्रम के माध्यम से एक सार्थक रूप दिया। उनके आश्रम में अतिथियों के लिए रहने और भोजन की मुफ्त में उत्तम व्यवस्था है।

विशेष है कि महाराज जी अपने खेतों में उपजे अन्न से ही अपने आगंतुकों को भोजन कराते हैं। भागम-भाग भरे जीवन के बीच कुछ दिन यहां आकर व्यक्ति को अध्यात्म और शांति का अनुपम अनुभव हो सकता है।

प्रकृति प्रेमी आध्यात्मिक लोग मध्य प्रदेश के सतना से यहां आ सकते हैं। सतना से प्रतिदिन एक बस यहां जाती है। इसके अलावा सतना के बस स्टैंड में स्थित परमहंस आश्रम की शाखा से भी यहां जाने के लिए जानकारी मिल सकती है। घनघोर जंगल, पर्वतों और झरनों के बीच स्थित परमहंस आश्रम में साधना के लिए योगी पुरुषों का आवागमन होते रहता है।

यहां आकर जीवन ठहर सा जाता है। मन को सुकून मिलता है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का तो कोई जवाब नहीं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहां का परमहंस आश्रम। पूज्य सच्चिदानंद जी के अध्यात्म ने धारकुंडी के सौंदर्य की महिमा को दैवीय बना दिया है। जिसका अनुभव प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों को जरूर लेना चाहिए।

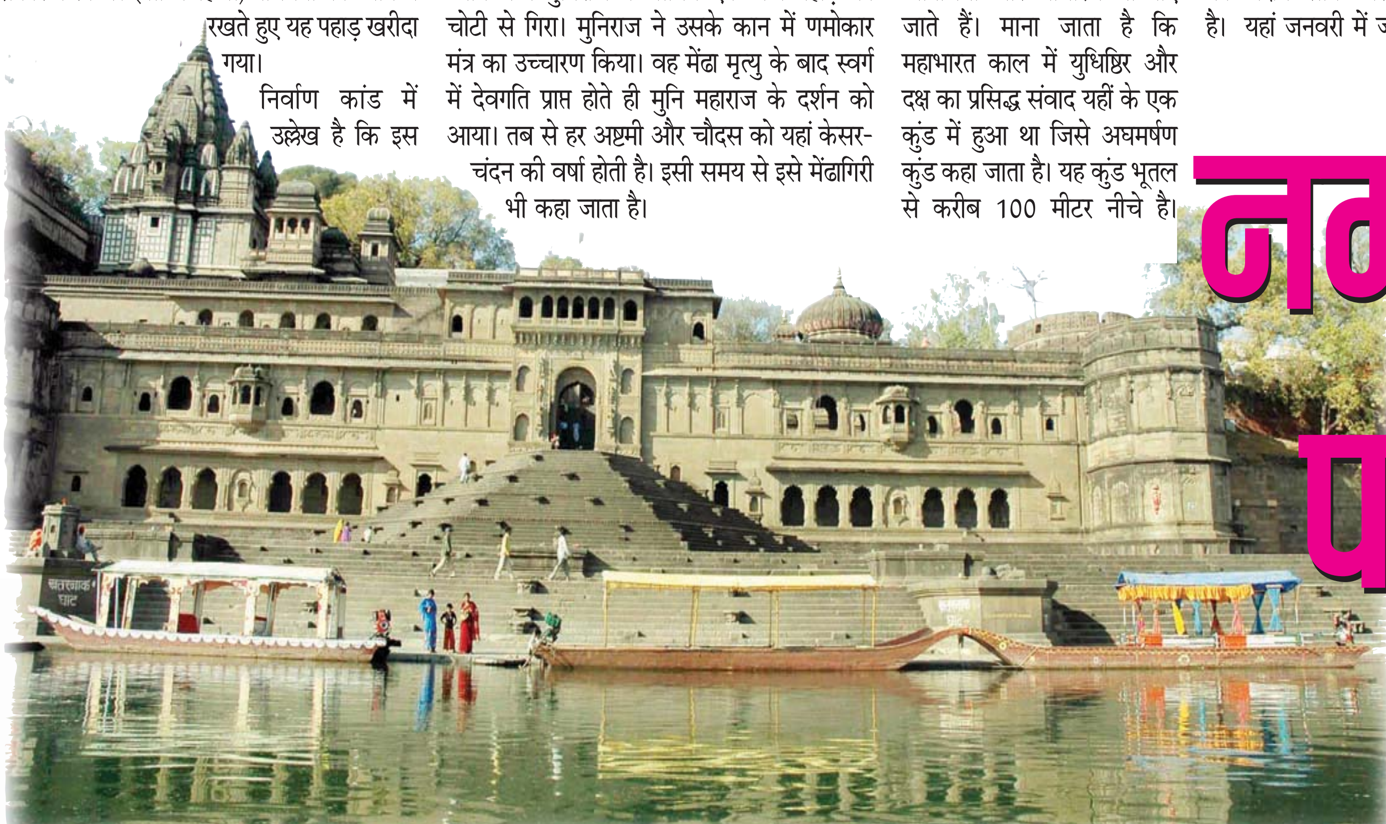

नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा धाराजी

देश में काशी ज्ञानभूमि, वृंदावन प्रेमभूमि और नर्मदा तट को तपोभूमि माना जाता है। संत डोंगरेजी महाराज गंगा में स्थान करने, जमुना में आचमन करने और नर्मदा के दर्शन करने का समान फल मानते थे।

पौराणिक और दर्शनीय स्थल धावड़ी कुंड

मालवावासी जिसे धाराजी के नाम से जानते हैं, वह धावड़ी कुंड देवास जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां संपूर्ण नर्मदा 50 फुट से गिरती है, जिसके फलस्वरूप पत्थरों में 10-15 फुट व्यास के गोल (ओखल के आकार के) गड्ढे हो गए हैं। बहकर आए पत्थर इन गड्ढों में गिरकर पानी के सहारे गोल-गोल घूमते हैं, जिससे घिस-घिसकर ये पत्थर शिवलिंग का रूप ले लेते हैं।

ऐसा लगता है जैसे नर्मदा स्वयं अपने आराध्य देव को आकार देकर सतत उनका अभिषेक करती हो। इन्हें बाण या नर्मदेश्वर महादेव का नाम दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धाराजी के स्वयंभू बाणों की प्राण-प्रतिष्ठा करना आवश्यक नहीं, ये स्वयंभू होकर प्राण-प्रतिष्ठित होते हैं।

इसी धाराजी पर चैत्र की अमावस पर मालवा, राजस्थान तथा निमाड़वासियों का प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लगभग लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं।

नर्मदाजी का यह सबसे बड़ा जलप्रपात वन प्रदेश में स्थित है। जलप्रपात से उत्तर में लगभग 10 कि.मी. पर सीता वाटिका, जिसे सीता वन भी कहते हैं, में सीता मंदिर भी स्थित है।

कहा जाता है कि यहा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और सीताजी ने यहां निवास किया था। यहां पर 64 योगिनियों और 52 भैरवों की विशाल मूर्तियां भी हैं। समीप ही सीताकुंड, रामकुंड और लक्ष्मणकुंड हैं।

सीताकुंड में हमेशा पेयजल उपलब्ध रहता है। सीता वाटिका से 16 कि.मी. पूर्व में कनेरी माता(जनश्रुति में जयंती माता) का मंदिर है, जिसकी तलहटी में कनेरी नदी बहती है, जिसमें विभिन्न रंगों की कनेर की झाड़ियां हैं।

यह स्थान पूर्णतः घने जंगल में से होकर यहां हिंसक पशुओं का वास भी है। सीतावाटिका से 6 कि.मी. की दूरी पर सीता खोह भी है, जिसके आसपास दुर्घटना से बचाव के लिए कंटीले तार लगा दिए गए हैं, जो इतनी गहरी है कि नीचे झांकने पर तलहटी नदी दिखाई देती है और पत्थर डालने पर आवाज नहीं आती है।

सीता वाटिका से लगभग 10 कि.मी. उत्तर में वनप्रदेश के रास्ते पोटला गांव (देवास जिला) से 1 कि.मी. की दूरी पर कावड़िया पहाड़ है।

जनश्रुति है कि महाभारतकाल में इस वन प्रदेश में पांडवों ने अज्ञातवास हेतु भ्रमण किया था और भीम ने 3 फुट व्यास के 10 से 30 फुट लंबी कॉलम-बीम आकार के लौह-मिश्रित पत्थर इकट्ठे किए थे, जो सात स्थानों पर सात पहाड़ियों के रूप में हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 40-45 फुट की है।

प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रो. वाकणकर ने भी पहाड़ियों के इन पत्थरों का अनुसंधान किया था। भीम का उद्देश्य इन पत्थरों से सात महल बनाने का रहा होगा, ऐसा माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले धावड़ीकुंड से चल कर इन पौराणिक और दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करते हुए तरानीया, रामपुरा, बखतगढ़ होते हुए चौबीस अवतार जाते हैं।

पुरातत्व, पर्यावरण, वनभ्रमण की दृष्टि से कावड़िया पहाड़, कनेरी माता, सीताखोह और धावड़ीकुंड (धाराजी) आकर्षण का केंद्र हैं, वही विहंगम दृश्यावलियों से पूर्ण पर्यटन स्थल है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सक्षिप्त खबर

चीन ने 8 दिन बाद किया था 5 भारतीय नागरिकों को रिहा, भारत ने उसके सिपाही को 2 दिन में ही छोड़ा

नई दिल्ली। भारत ने जिस चीनी सैनिक को लद्दाख में पकड़ा था, उसे सुरक्षित लौटा दिया है। भारतीय सेना ने चीन को उसके सैनिक को लौटा दिया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर लद्दाख आ गया था। मंगलवार रात (20 अक्टूबर) को चुशूल मोल्दो में बैठक स्थल पर पीएलए के सिपाही कॉर्पोरल वांग हां लॉन्ग को चीनी सेना को सौंप दिया। भारत ने महज दो दिन के भीतर ही चीन को उसके सैनिक को वापस कर दिया। मगर ये वही चीन है जिसने भारत के पांच नागरिकों को छोड़ने में आठ दिन का समय लगाया था। दरअसल, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उसका एक सिपाही रविवार (18 अक्टूबर) रात को सीमा के पास से लापता हो गया। इसके बाद चीनी सेना ने भारत से अपने सैनिक को लौटाने की गुहार लगाई थी। पकड़े गए चीनी सैनिक के बारे में भारतीय सेना ने कहा था कि उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में सोमवार को पकड़ा है। पश्चिमी थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने सोमवार रात को लापता पीएलए सैनिक को लेकर कहा कि हमारा एक चीनी सिपाही उस वक्त लापता हो गया, जब वह 18 अक्टूबर की रात एक चरवाहे को अपना खोए हुए याक को खोजने में मदद कर रहा था। कर्नल झांग ने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद ही चीनी सीमा रक्षकों ने भारतीय पक्ष को घटना की सूचना दे दी थी। हालांकि, भारत ने प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी पूछताछ कर दो दिन के भीतर यानी 20 अक्टूबर की रात को चीन के सैनिक को सुरक्षित वापस लौटा दिया। लेकिन जब 4 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के पांच नागरिक सीमा पर रास्ता भूल गए थे, तो चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि, चीन ने उन पाचों भारतीय नागरिकों को 12 सितंबर को भारत को वापस लौटा दिया, मगर चीन ने इसके लिए आठ दिन का समय लगाया। लेकिन जब चीनी सैनिक के पकड़े जाने की बात आई तो भारत ने दरियादिली दिखाई और त्वरित एक्शन लेते हुए उसने चीन को उसका सैनिक महज दो दिन के भीतर ही छोड़ दिया। इन पाचों भारतीय नागरिकों के चीन द्वारा पकड़े जाने की सूचना सबसे पहले भारतीय पक्ष में कांग्रेस विधायक निनॉन्ग इरिंग ने दी थी और उन्होंने कथित तौर पर चीन द्वारा आगवा किए जाने की बात कही थी।

क्या कहता है नियम

दो देशों के बीच सीमा पर जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, उसके मुताबिक, शांति काल में जब भी किसी देश का सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है और उससे पूछताछ होती है। फिर उसके इरादे का पता लगाया जाता है। पूछताछ में जब पकड़े गए शख्स की शिनाख्त हो जाती है और अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके पकड़े जाने की सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है। प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद और पूछताछ में संतुष्ट होने के बाद संबंधित देश के सैनिक को लौटा दिया जाता है।

क्या पाकिस्तान FTF की 'ग्रे सूची' से निकल सकता है या नहीं? जानें क्या कहती है नई रिपोर्ट

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की 'ग्रे सूची' में संभवत: बना रहेगा क्योंकि वैश्विक निगरानी कार्य योजना द्वारा दिए गए 27 लक्ष्यों में वह छह का अनुपालन करने में असफल रहा है। यह दावा बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों में किया गया।

उल्लेखनीय है कि आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन को रोकने एव निगरानी करने वाली पेरिस से संचालित संस्था की 21 से 23 अक्टूबर के बीच डिजिटल माध्यम से वार्षिक बैठक होगी जिसमें 27 बिंदुओं की कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। एफ एटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में 'ग्रे सूची में डाला था और इस्लामाबाद को धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की 27 बिंदुओं की कार्य योजना को वर्ष 2019 के अंत तक लागू करने को कहा था , लेकिन कोविड महामारी की वजह से इस मियाद में वृद्धि कर दी गई।

भारत-ताइवान में ट्रेड वार्ता की रिपोर्ट्स पर घबराया चीन, दे डाली गीदड़भभकी

बीजिंग। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया दुखी है। लगभग रोजाना ही चीन अपने सैनिकों के जरिए से पड़ोसियों के साथ विवाद पैदा करता रहता है। लद्दाख में जहां पिछले कई महीनों से भारत के साथ आमने-सामने की स्थिति में है तो वहीं, ताइवान के साथ भी ड्रैगन का विवाद काफी पुराना है। अब चीन ने ताइवान को लेकर भारत को गीदड़भभकी दी है। चीन ने भारत में चल रहीं उन मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताई है, जिनमें कहा गया था कि भारत-ताइवान के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। बीजिंग ने कहा है कि भारत को वन-चाइना पॉलिसी के साथ प्रतिबद्ध रहना चाहिए और विवेकपूर्ण तरीके के साथ ताइवान को डील करना चाहिए। इसके अलावा, चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में तिब्बत मामलों के लिए नियुक्त किए गए अमेरिकी अधिकारी की तिब्बत सरकार के साथ बैठक को भी आड़े हाथों लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ''दुनिया में वन-चाइना पॉलिसी है और ताइवान चीन का नायाब हिस्सा है।

भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वन-चाइना पॉलिसी को लेकर सर्व-सहमति है।'' झाओ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि भारत आने वाले समय में ताइवान के साथ ट्रेड पर बातचीत शुरू कर सकता है। झाओ ने कहा, ''यह (वन-चाइना पॉलिसी) चीन का अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करने का राजनीतिक आधार भी है। इसलिए, हम चीन और ताइवान के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच किसी भी आधिकारिक आदान-प्रदान या किसी भी आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का पूरी दृढ़ता से विरोध करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारतीय पक्ष को वन-चाइना प्रिंसिपल के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और ताइवान से संबंधित मुद्दों पर विवेकपूर्ण और ठीक से विचार करना चाहिए। पिछले कुछ समय से चीन और ताइवान के बीच में कई मुद्दों पर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में ताइवान ने नेशनल डे भी मनाया है, जिसको लेकर चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया कवरेज के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। चीन ने कहा था कि ताइवान के नेशनल डे का कवरेज करते समय भारतीय मीडिया वन-चाइना पॉलिसी का ध्यान रखे और ताइवान को देश न बताए। चीन ने आगे कहा था कि सभी देशों को बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने चाहिए वन-चाइना पॉलिसी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए। बीजिंग का समय-समय पर ताइवान और भारत सहित विदेशी

देशों के बीच विकसित हो रहे संबंधों को लेकर आक्रामक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता रहा है। फरवरी 2017 में, चीन ने भारत के साथ ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसमें नई दिल्ली को वन-चाइना पॉलिसी का पालन करने की नसीहत दी गई थी और ताइपे के साथ कोई आधिकारिक संपर्क नहीं रखने के लिए कहा गया था। वहीं, सितंबर 2015 में, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनने से पहले, त्साई ने ताइवान की विदेश नीति में भारत के बढ़ते महत्व के बारे में बात की थी।

मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान संग हिस्सा लेगा ऑस्ट्रेलिया, यह बोला चीन

बीजिंग। चीन ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत की इस घोषणा का संज्ञान लिया है कि अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। उसने कहा कि सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। भारत ने सोमवार को ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया आगामी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेगा जिसका तात्पर्य है कि चतुष्पक्षीय गठबंधन (QUAD) के सभी चारों सदस्य देश इस महाभ्यास में भाग लेंगे। अमेरिका और जापान अन्य दो देश हैं जो इस वार्षिक अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस अभ्यास के होने की संभावना है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने 'इस घटनाक्रम का संज्ञान' ले लिया है। उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा, ''हमारा सदैव मानना रहा है कि देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए अनुकूल होना चाहिए।'' इस विशाल सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने के ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध पर ध्यान देने का भारत का निर्णय ऐसे वक्त आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन के साथ रिश्ता तनावपूर्ण हो गया है। चीन के मन में इस मालाबार अभ्यास के उद्देश्य को लेकर आशंका उत्पन्न हो गई है क्योंकि वह महसूस कर रहा है कि यह वार्षिक युद्धाभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके दबदबे पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है। मालाबार अभ्यास 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान 2015 में इस अभ्यास का स्थायी हिस्सेदार बना। वर्ष 2018 में यह अभ्यास फिलीपन सागर में गुआम तट के पास और 2019 में यह जापान तट के पास हुआ था। पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास से जुड़ने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के आलोक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति वैश्विक शक्तियों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय है।

नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पर पाक में बवाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफ्दर की गिरफ्तारी से वहां की सियासत में बवाल हो गया है। दरअसल, सोमवार को कराची में हुई एक संयुक्त रैली के बाद नवाज शरीफ के दामाद सफदर को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बाद में बेल पर रिहा भी कर दिया गया। मगर इसे लेकर पाकिस्तान में ऐसा भूचाल आया कि अब पुलिस भी इमरान सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है।

सफदर की गिरफ्तारी में पाकिस्तान में सेना के हस्तक्षेप के खिलाफ पुलिस खुलकर मैदान में है और आईजी समते ज्यादातर पुलिस वालों ने मास लीव के लिए अप्लाई किया है। हालांकि, अब मामला शांत कराने की कोशिश सेना की ओर से जारी है। नौबत यहां तक आ गई कि भारी विरोध को देखते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जवाब बाजवा ने सफ्दर की गिरफ्तारी के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

जीओ टीवी के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को करांची पुलिस के कमांडर को आदेश दिया कि मोहम्मद सफ्दर की गिरफ्तारी क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। दरअसल, यह आदेश तब आया जब पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जनरल बाजवा और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी मामले की जांच करने की अपील की थी।

आईजी का अपहरण

जीओ टीवी के मुताबिक, सफदर की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में बगावत सिंध पुलिस और सेना बीच जंग सा माहौल है।

सफदर के खिलाफ पुलिस पर शिकायत दर्ज करने के लिए दबाव डाले

जाने की खबरों को पर बिलावल ने कहा कि सिंध में हर पुलिस अधिकारी, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक सभी सोच रहे थे कि रविवार रात 2 बजे आईजी सिंध मुश्ताक महर के दफ्तर को किसने घेर लिया था?

सिंध पुलिस का कहना है कि कैप्टन सफदर को जब गिरफ्तार किया गया, तब सिंध पुलिस के आईजी सिंध मुश्ताक महर को उनके दफ्तर में घेर लिया गया था। जिसके बाद ही कैप्टन सफदर की गिरफ्तार हुई। बताया जा रहा है कि सिंध सरकार को भी इस गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी।

सिंध की पीपीपी सरकार को भी भनक नहीं

विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफदर की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सिंध प्रांत की पीपीपी सरकार को भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस भी आश्चर्यचकित थी कि सोमवार तड़के आखिर वो कौन लोग थे, जिन्होंने सिंध पुलिस प्रमुख के घर को घेर रखा था और किसने सफदर की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

पुलिस अधिकारियों का छुट्टी पर जाने का फैसला

इस घटना के बाद पुलिस में बगावत शुरू हो गई। पुलिस के अधिकारों का हनन करने का हवाला देते हुए आईजीपी मुश्ताक महर के छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। मुश्ताक महर के इस ऐलान के बाद सिंध के कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने छुट्टी का आवेदन दिया। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना सिंध प्रांत की पुलिस का मजाक उड़ाने वाली है। जिसमें उन्हें गिरफ्तारी की भनक भी नहीं लगी। बताया जा रहा है कि करीब 12 से 13 शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने लीव के लिए अप्लाई किया है। हालांकि, सिंध प्रांत के सरकार ने अधिकारियों से आवेदन वापस लेने की अपील की है।

क्या है मामला

दरअसल, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में 11 विपक्षी दलों के महागठबंधन 'पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट' का 18 अक्टूबर को एक जलसा हुआ था।

सफदर और उनकी पत्नी, पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज विपक्षी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए शहर आए थे। उन्हें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के प्रति असम्मान जताने के आरोप में होटल से गिरफ्तार किया गया। मरियम और पीएमएल-एन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सफदर वापस लाहौर चले गए लेकिन सिंध प्रांत में सत्तारूढ़ पीपीपी ने घटनाक्रम से खुद को अलग करते हुए हैरानी जताई कि सफदर की गिरफ्तारी का आदेश किसने दिया था।

नवाज का इमरान सरकार पर हमला

सिंध पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के छुट्टी पर जाने की बात पर नवाज शरीफ ने ट्वीट कर इमरान सरकार पर हमा बोला। उन्होंने ट्वीट किया, 'कराची की घटना से इस विचार को बल मिलता है कि पाकिस्तान में राज्य से ऊपर राज्य है। आपने प्रांतीय सरकार को मिले जनमत का मजाक उड़ाया, परिवार की निजता को तार-तार कर दिया, अपने आदेश को मनवाने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी को अगवा किया। हमारी सेना की छवि खराब कर दी। आईजीपी का पत्र इस बात की तस्दीक करता है कि आपने संविधान को ताक पर रख दिया।'

पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गिलगित-बाल्टिस्तान', प्रदर्शनकारियों ने की राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग

बाल्टिस्तान। एक प्रमुख स्थानीय एक्टिविस्ट बाबा जान सहित राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग को लेकर गिलगित-बाल्टिस्तान में तीसरे सप्ताह भी प्रदर्शन जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस कानून पर सवाल उठाए, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान और उसके कानूनों का हिस्सा नहीं है। इन कानूनों का यहां इस्तेमाल नहीं करें। यहां तक कि क्षेत्र के दूरदराज के गांवों के लोग भी अब इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। जो अवैध सजा काट रहे हैं।

90 वर्षीय बाबा जान की तस्वीरें लेकर, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए और राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। 2011 में गिरफ्तार किए गए बाबा जान एक एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रशासन को चुनौती दी थी, जो कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के खिलाफ काम कर रहा था।

अब सांसों के परीक्षण से एक मिनट में चलेगा पता कोरोना संक्रमण है या नहीं

एजेंसी, सिंगापुर। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने एक सांस परीक्षण विकसित किया है, जो केवल एक मिनट में बता देगा कि उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) के शोधकर्ताओं के अनुसार एक व्यक्ति को बस एक लंबी सांस एक डिस्पोजेबल मुखपत्र में छोड़नी होगी। यह डिस्पोजल मास स्पेक्ट्रोमीटर से जुड़ा होता है। यह सांस परीक्षण (ब्रीथ टेस्ट) में व्यक्ति की सांस में मौजूद वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) का पता लगाता है।

रोग की 90 फीसदी सटीक पहचान

मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के जरिए इन यौगिकों का विश्लेषण करने के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता के साथ की जाती है। शोधकर्ताओं ने 180 लोगों पर यह परीक्षण किया है। इस तकनीक को एनयूएस के स्टार्टअप ब्रीथोनिक्स के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। उनके मुताबिक इस परीक्षण के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण की पहचान करने के लिए एक तेज और सुविधाजनक समाधान मुहैया हो सकेगा।

इजराइल ने कोरोना टीके को लेकर अब क्या कहा? अगस्त में किया था वैक्सीन बनाने का दावा

एजेंसी, यरूशलम। इजराइल के कोविड-19 टीके 'ब्रिलाइफ' का मानव परीक्षण अक्तूबर के आखिर तक शुरू होगा। इजराइली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज ने टीके के मानव परीक्षण की शुरुआत के बारे में कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण और राष्ट्रीय गौरव की बात है। यह देश-दुनिया के लिए एक बड़ी खबर ला सकता है। यह टीका इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने विकसित किया है। इजराइल ने अगस्त में दावा किया था कि उसके पास कोरोना वायरस का टीका है, लेकिन इसे नियामक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। गैंट्ज सोमवार को आईआईबीआर पहुंचे, जहां उन्हें टीके के मानव परीक्षण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। स्टाफ ने शानदार काम किया है। मैं आईआईबीआर के सभी अनुसंधानकर्मियों और प्रशासकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आईआईबीआर के निदेशक शैम्यूल शापिरा ने इस दौरान संभावित टीके के नाम ब्रिलाइफ का अनावरण किया।

कोरोना से ठीक होकर दूसरी बीमारियों से घिर सकते हैं

वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लोग कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई दूसरी बीमारियों से घिर सकते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, कोरोना महामारी के आधे से अधिक रोगियों ने अपने प्रारंभिक संक्रमण के बाद दो से तीन महीने तक सांस की तकलीफ थकान, चिंता और अवसाद जैसे लक्षणों का अनुभव किया है। शोध में 58 रोगियों में कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभाव को देखा गया, जो महामारी की बीमारी से ग्रस्त हुए थे। इसमें पाया गया कि कुछ रोगियों में संक्रमित होने से लगातार बुखार के कारण शरीर के अंगों में कुछ महीनों तक समस्या बनी रहती है। हालांकि, इस अध्ययन को अन्य वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षा के पहले ही मेड-आरएक्सआईवी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया था।

पाक में कोरोना से मरने वालों की दर 140 फीसदी क्यों बढ़ी? मंत्री ने दिया यह जवाब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों के घोर उल्लंघन की वजह से गत हफ्तों के मुकाबले संक्रमण से मृत्युदर में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर ने कहा कि यह लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर वे ऐसा ही व्यवहार जारी रखेंगे तो जान और जीविकोपार्जन दोने से हाथ धो बैठेंगे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में गत 24 घंटों में कोविड-19 से 19 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक महामारी से 6,692 लोगों की जान चुकी हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गठित राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र (एनसीओसी) के प्रमुख की भी जिम्मेदारी निभा रहे उमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि आधिकरिक दिशानिर्देशों को नजरअंदाज करने की सामूहिक चूक की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने मंगलवार रात को ट्वीट कर कहा, ''पिछले हफ्ते रोजाना कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 12 थी। यह पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले 140 प्रतिशत अधिक है। अगर हमने मौजूदा रास्ते को नहीं बदला तो हम जीवन और जीविकोर्पाजन दोनों को खो देंगे।'' इस बीच, मंत्रिमंडल ने देश में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है और लोगों को महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका के मद्देनजर सभी एहतियात बरतने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गत 24 घंटे में 660 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 3,24,744 हो गई है जिनमें से 3,08,674 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 559 लोगों की हालत गंभीर है।

महाराष्ट्र से सूरत आ रही बस 40 गहरी खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत, 35 जख्मी

सूरत महाराष्ट्र के जलगांव से सूरत आ रही निजी ट्रावेल्स कंपनी की एक बस 40 गहरी खाई में जा गिरीं। इस हादसे में 4 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 35 जितने लोग घायल हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव से यात्रियों को लेकर दक्षिण गुजरात के सूरत की ओर रवाना हुई निजी ट्रावेल्स कंपनी की लग्जरी बस रात करीब 2 बजे कोंडाईभारी घाटी के निकट 40 फूट गहरी खाई में जा गिरीं। इस हादसे में बस में सवार 4 यात्रियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 35 से यात्रियों के घायल होने की खबर है। घायलों में सूरत और जलगांव के लोग शामिल हैं। बस के ड्राइवर को गंभीर हालत में विसारवाडी रूरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नंदुरबार जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि टायर फटने की वजह से बस बेलगाम हो गई और यात्रियों के साथ गहरी खाई में जा गिरी। घायलों में सभी प्रवासी मजदूर थे, जो जलगांव से सूरत आ रहे थें।

दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी सुनवाई : जाडेजा

गांधीनगर गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने आज स्पष्ट किया कि दुष्कर्म की घटनाओं को दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई होगीद्य ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सबक मिलेद्य पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर गांधीनगर के कराई पुलिस अकादमी में गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा और पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया की अध्यक्षता में परेड का आयोजन किया गया थां। जिसमें सेवा के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजंलि दी गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए गृह राज्यमंत्री जाडेजा ने कहा कि बनासकांठा के डीसा में 12 वर्षीय मूक-बधिर किशोरी से रेप और हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी और उसके लिए सरकार स्पेशल पब्लिक

प्रोसिक्युटर की नियुक्ति करेगीं। दुष्कर्म के दोषियों को कडी से कड़ी सजा दिलाने को सरकार को कटिबद्ध हैं।

मूक-बधिर किशोरी से रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हैं। मृतक और आरोपी सगे मामा-बुआ की संतान थे।

गौरतलब है मूक-बधिर किशोरी की हत्या के मामले में डीसा के विधायक शशीकांत

क्रांति समय फाउंडेशन (NGO)

पंड्या के नेतृत्व में गृह राज्यमंत्री से पेशकश कर दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग की गई थी। डीसा के लोगों ने भी पूरा मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने के साथ स्पेशल वकील देने की मांग की थीद्य इसके अलावा जांच के लिए एसआईटी गठित करने की भी पेशकश की गई थीं।

गृह राज्यमंत्री ने सभी मांग स्वीकार करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया था।

चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता से सभी यात्री सुरक्षित

सूरत शहर के भगवान महावीर कॉलेज के निकट से गुजर रही सिटी बस में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गईं।

आग लगते ही ड्राइवर ने बस को तुरंत रोक सभी यात्रियों को नीचे उतार दियां।

घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पायां। जानकारी के मुताबिक सूरत में सिटी लिंक की सीएनजी बस यात्रियों को लेकर शहर के भगवान महावीर कॉलेज के निकट से गुजर रही थीं। उस वक्त अचानक बैटरी में स्पार्क हुआ बस में आग लग गईं। आग लगते ही ड्राइवर तुरंत बस साइड में खड़ी कर दी और यात्रियों के साथ नीचे उतर गयां। बस में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल स्वरूप धारण कर लिया और पूरी बस धू धू कर जल उठीं। खबर मिलते ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच और आग पर काबू पा लियाद्य राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुईं। हांलाकि आग में बस जलकर खाक हो गईं।

राज्य में 1137 नए केस, 9 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 89.03 प्रतिशत

अहमदाबाद राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रमाण धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य में 1137 नए केसों के साथ कोरोना केसों का कुल आंकड़ा 162985 पर पहुंच गया है।

24 घंटों में 1180 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया हैद्य जबकि 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में सूरत कॉर्पोरेशन में 169, अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 165, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 77, सूरत में 70, राजकोट कॉर्पोरेशन में 69, मेहसाणा में 48, वडोदरा में 41, जामनगर कॉर्पोरेशन में 40, रा. जकोट में 35, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 29, कच्छ में 26, पाटन में 26, जामनगर में 25, भरुच में 23, दाहोद में 23, पंचमहल में 22, साबरकांठा में 22 और सुरेन्द्रनगर में 20 समेत राज्यभर में कोरोना के कुल 1137 नए केस सामने आए।

जबकि 1180 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं।

इस दौरान अहमदाबाद कॉर्पोरेशन और सूरत कॉर्पोरेशन में 2-2, बनासकांठा, भरुच, गिर सोमनाथ, सूरत और वडोदरा कॉर्पोरेशन में 1-1 समेत राज्य में कुल 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज 52986 समेत राज्यभर में अब तक कुल 5532522 लोगों का टेस्ट किया गया।

जिसमें 162985 कोरोना संक्रमित सामने आएं।

राज्य में अब तक 145107 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और 3663 मरीजों की मौत हो चुकी है।

फिलहाल राज्य में 14215 एक्टिवस केसों में 14140 मरीजों की हालत स्टेबल है और 75 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं।

राज्य के विभिन्न जिलों में आज की तारीख में 538809 लोगों को कोरन्टाइन में रखा गया है।

जिसमें 538553 होम कोरन्टा. इन और 256 लोगों को फैसिलिटी कोरन्टाइन में रखा गया है।

गुजराती फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया कोरोना संक्रमित

गुजराती फिल्मों के मशहूर अभिनेता और भाजपा नेता नरेश कनोडिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजि. टिव आने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया हैद्य नरेश कनोडिया के पुत्र हितु कनोडिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता में कोरोना के लक्षण

दिखनेके बाद जांच कराई गईं। जिसके बाद सिटी स्केन में उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार के लिए अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। 20 अगस्त 1943 को मेहसाणा जिले के कनोडा गांव में जन्मे नरेश कनोडिया गुजराती फिल्मों के सफल अभिनेता के साथ कुशल संगीतकार भी हैं। नरेश कनोडिया ने 1970 में आई गुजराती फिल्म वेलीने आव्या फूल से बतौर अभिनेता अपने कैरियर की शुरुआत की थीं। उसी साल गुजराती फिल्म जीगर अने अमी में भी कनोडिया ने छोटा सा किरदार निभाया थां।

डीआरएम ऑफिस अहमदाबाद द्वारा मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार झा की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्री झा द्वारा अहमदाबाद मंडल की त्रैमासिक वेब पत्रिका राजभाषा ''आश्रम सौरव'' के ''बत्तीसवें'' वे अंक का विमोचन किया गया। प्रत्येक तिमाही में आयोजित कवि लेखकों की जयंती समारोह के आयोजन की श्रंखला में रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और राजभाषा विभाग द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन पर पावर पॉइंट के माध्यम से एक रोचक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर श्री झा ने उपस्थित सभी शाखा अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन पर अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व है। हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक डिक्टेशन पत्राचार तथा कंप्यूटर पर हिंदी में किया जाए व रेलकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए।अपना दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में सहज, सरल, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग स्वयं करें/कराएं। मूलरूप से हिंदी में काम करें तथा तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखे। हिंदी में प्रवीण अधिकारी एवं कर्मचारी शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करें तथा राजभाषा पैरा अपने निरीक्षण नोट में आवश्यक रूप से सम्मिलित करें। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा की और निर्धारित लक्ष्य तक ही सीमित न रहकर, उससे भी अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में करने और अधीनस्थों के लिए उदाहरण बनने का आव्हान किया। सभी सदस्यों को कहा कि आज के डिजिटलदौर में हिंदी में कार्य, प्रचार व प्रसार के लिए कंप्यूटर सरल व सशक्त माध्यम है जिनके द्वारा कंप्यूटरों पर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कार्य को और गति प्रदान करने/ कराने का आग्रह भी किया। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री अनंत कुमार ने माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबंधी मंडल रेल प्रबंधक द्वारा ध्यान में लाई गई विभिन्न मदों पर विशेष ध्यान देने व कार्रवाई करने हेतु जोर दिया तथा बैठक के अंत में दिशा-निर्देश एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। राजभाषा अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। श्री प्रकाश पटेल ने बैठक का सफलतापूर्वक संचालन किया। प्रत्येक तिमाही की भाँति इस अवसर पर, हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा ''राजभाषा रत्न'' नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। श्री बी एन नागर, श्री अमित सिंह राठौड़, श्री शैलेंद्र देसाई एवं श्री उपेंद्र कुमार गुप्ता कार्यक्रम की सफलता के आधार रहे।

सार-समाचार

मां ने थप्पड़ मारा तो 6 साल की बच्ची घर छोड़ चली गई

सूरत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई हैद्य जहां एक मां ने मामूली सी गलती पर बेटी को थप्पड़ मार दियाद्य मां के थप्पड़ से नाराज 6 साल की बच्ची घर छोड़कर चली गई। सोमवार से लापता बच्ची को लेकर माता-पिता परेशान हैं। पुलिस ने माता की शिकायत के आधार पर फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत के पांडेसरा गोवालक रोड क्षेत्र के योगीनगर में 35 वर्षीय गणेश गुदरीभाई यादव परिवार के साथ रहते है। सोमवार को गणेश यादव की पत्नी सोना यादव पूजा कर रही थी, उस वक्त निकट खेल रही 6 साल की बेटी शीतल से पानी ढुल गया। गुस्से में आकर गणेश यादव की पत्नी ने शीतल को थप्पड़ मारते हुए फटकार लगाई। मां की फटकार और थप्पड़ से नाराज शीतल बगैर किसी को कुछ बताए घर से छोड़कर चली गई। हांलाकि एक घंटे तक सोना को घर में नहीं देख सोना यादव ने उसकी खोजबीन शुरू की, परंतु उसका कहीं अता पता नहीं मिलने पर अपने पति गणेश यादव को बताया। घर पहुंचने के बाद गणेश यादव ने अड़ौस-पड़ौस समेत नाते-रिश्तेदारों के यहां शीतल की तलाश की। परंतु शीतल के कहीं नहीं मिलने पर पुलिस थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। सोना यादव की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर शीतल की तलाश शुरू की है।

जखणिया गांव में पत्नी और तीन पुत्रियों की हत्या कर पति फरार

कच्छ मांडवी तहसील के जखणिया गांव में एक शख्स अपनी पत्नी और पुत्रियों की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक कच्छ जिले की मांडवी तहसील के जखणिया गांव में जखु उर्फ शिवजी पाचाण अपनी पत्नी भावना, 10 वर्षीय पुत्री दुप्ती, 5 वर्षीय किंजल और 2 वर्षीय धर्मिष्ठा के साथ रहता है।

जखु पाचाण ने पत्नी भावना को जहरीली दवाई पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपनी तीनों बेटियों की तीक्ष्ण हथियार से हत्या करने के बाद जखु पाचाण फरार हो गया। छोटे से गांव में एक साथ चार लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। खबर लगते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस ने घटना के बाद फरार जखु पाचाण की तलाश शुरू की है।

जेतपुर में दिन दहाडे नकद और आभूषण समेत 42 लाख की लूट

राजकोट जिले के जेतपुर में आज सुबह दो लाख रुपए नकद और सोने के आभूषणों समेत रु. 42 लाख की लूट से सनसनी फैल गईं। यह घटना उस समय हुई जब धोराजी का व्यापारी जेतपुर में आभूषण बेचने जा रहा थां। अज्ञात शख्सों के हमले में घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक राजकोट के धोराजी निवासी चिमन कालाभाई वेकरिया नामक व्यापारी सोने-चांदी के आभूषणों का व्यापारी है। पिछले तीन साल से चिमन वेकरिया राजकोट के जेतपुर स्थित व्यापारियों को आभूषण बेचने आता था। हमेशा की तरह चिमन वेकरिया आज सुबह जेतपुर के सर्राफा बाजार से मतवा गली की ओर पैदल जा रहे थे। उस वक्त करीब 25 साल की उम्र के दो शख्सों ने चिमन वेकरिया को घेर लिया और आंख मिर्च पाउडर डालकर रुपए और आभूषणों से भरा बैग खींचने का प्रयास किया। चिमन वेकरिया के प्रतिकार करने पर अज्ञात शख्सों ने उन पर चाकू से हमला कर दियाद्य चिमन वेकरिया के गिरते ही अज्ञात शख्स दो लाख रुपए नकद और 40 लाख के आभूषणों से भरा बैग छीनकर मोटर साइकिल पर फरार हो गए।

हमले में घायल चिमन वेकरिया को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जेतपुर पुलिस ने चिमन वेकरिया की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू की है।

दक्षिण-मध्य गुजरात समेत सौराष्ट्र में सामान्य से हलकी बारिश की संभावना

अहमदाबाद मौसम विभाग ने आगामी दो दिन मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य से हलकी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद आगामी दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। आज गांधीनगर में हुए वेधर वॉच ग्रुप के वेबीनार के बाद राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने बताया कि मंगलवार की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के 17 जिलों की 28 तहसीलों में बारिश हुई है। जिसमें सबसे अधिक गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़डा तहसील में 54 मिमी बारिश दर्ज हुई। राज्य में 20 अक्टूबर 2020 तक 1134.33 मिमी बारिश हो चुकी है। जो पिछले 30 वर्ष में राज्य की औसत 831 मिमी के मुकाबले 136.50 प्रतिशत हैद्य कृषि विभाग के मुताबिक जारी वर्ष में 12 अक्टूबर 2020 तक राज्य में करीब 87.24 लाख हेक्टर में खरीफ फसलों की बुवाई हुई है। जो गत वर्ष इसी समयावधि के दौरान 86.77 लाख हेक्टर में बुवाई हुई थी। इस साल पिछले तीन वर्ष की औसत बुवाई के मुकाबले 102.76 प्रतिशत बुवाई हुई है। सिंचाई विभाग के मुताबिक सरदार सरोवर जलाशय में 302152 एमसीएफटी पानी जमा हुआ है। जो कुल संग्रह शक्ति का 90.44 प्रतिशत है। राज्य के 534303 एमसीएफटी पानी का संग्रह हुआ है जो कुल संग्रह क्षमता का 95.92 प्रतिशत है। फिलहाल राज्य में 179 डैम हाई अलर्ट पर, 11 बांध अलर्ट पर और वॉर्निंग पर 8 जलाशय हैं।

बच्चों की मदद से चोरी की घटना को अंजाम देता गिरोह कानून के शिकंजे में

भरुच (ईएमएस)द्य भरुच की सी डिवीजन पुलिस ने बच्चों की मदद से चोरी की घटना को अंजाम देनेवाले गिरोह के तीन शख्सों को गिरफ्तार कर लिया है। त्रिची नामक यह गिरोह वाहनों को टार्गेट करता और उनकी रेकी कर वाहन के खड़े होते ही उसमें रखी बैग बच्चों की मदद से उड़ा लेता। दरअसल भरुच के जीएनएफसी रोड पर तीन दिन पहले एक शख्स अपनी कार रोड पर पार्क कर निकट की दुकान में गया था। उस वक्त कार में रु. 80000 से भरी बैग रखी हुई थी। शख्स वापस लौटा तो कार से रुपयों से भरी बैग गायब थी। शख्स की शिकायत के आधार पर भरुच सी डिवीजन पुलिस ने मामला दर्ज किया और शहर की प्रमुख सड़कों पर नेत्रम प्रोजेक्ट के तहत लगे सीसीटीवी फूटेज को खंगालना शुरू किया। जिसमें दो मोटर साइकिलों पर बच्चों समेत चार लोगों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया होने का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फूटेज के मुताबिक एक बच्चा कार के पास खड़ा रहता है और अन्य एक शख्स कार का दरवाजा खोलकर रवाना हो जाता है। दरवाजे के खुलते ही कार के निकट खड़ा बच्चा रुपयों से भरी बैग उठा लेता है और मोटर साइकिल पर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। फूटेज में नजर आ रही मोटर साइकिल के नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही उसे सफलता भी मिली। पुलिस ने सुब्रह्मण्यम नायडु, दीपक नायडु और रमेश सुरेश नायडु को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वह अब तक भरुच में 3, अंकलेश्वर में 2, नवसारी में 1 और कामरेज में 1 समेत 7 जितनी चोरी को घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। भरुच के डीवीवायएसपी विकास सुंडा के मुताबिक त्रिची गिरोह वाहनों को टार्गेट कर उनका पीछा करता है। वाहन के खड़े होते ही बच्चे की मदद से रुपयों समेत कीमती सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया

जाता है।

बच्चा यदि पकड़ा जाता है तो उसका वयस्क साथी फरार हो जाता है। बच्चों के साथ कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की जाती है, इसलिए गिरोह के वयस्क शख्सों के पकड़े जाने का डर कम होता हैं।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कांग्रेस-राजद पर राजनाथ का तंज, कहा- लालटेन फूट गई है और तेल बह गई, अब न पंजा के चली और न...

कहलगांव (भागलपुर)। (एजेंसी)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोडी की तरह ही भाजपा-जदयू का गठबंधन है तथा इस बात पर तो बहस की जा सकती है कि बिहार में गठबंधन सरकार द्वारा कितना विकास किया गया किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठा सकता। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक चुनावी रैली में राजनाथ ने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि लोगों ने इसके 15 साल के कार्यकाल को देखा है तथा उसके कुशासन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के ''सुशासन'' के बीच के अंतर को देखा जा सकता है। राजनाथने 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा और जदयू का गठबंधन भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन और सहवाग की शुरुआती जोड़ी के रूप में सुपरहिट है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने बिजली, सड़क और पानी की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसकी बिहार में दशकों से कमी थी। राजनाथ ने कहा, लोगों ने लालटेन (राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन) के 15 साल के शासन को देखा है और उन्होंने भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार के दौरान बिहार के विकास को भी देखा है। इन दोनों सरकारों के प्रदर्शन की तुलना नहीं की जा सकती है। राज्य राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान बदल गया। राजद और कांग्रेस पर राजनाथ ने भोजपुरी में ही तंज कसा तो सभा तालियों से गूंज उठी। राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां लालटेन फूट गई है, तेल बह गई। अब ना पंजा का चली ना उनकर कोई खेल चली।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सुशील मोदी की प्रशंसा करते हुए राजनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं। उन्होंने ने कहा, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए सब कुछ किया है। इस पर बहस हो सकती है कि क्या उन्होंने पर्यात काम किया है या कम काम किया है या अधिक किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई बहस नहीं हो सकती है। राजनाथ ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर उंगली नहीं उठा सकता। राजनाथ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने न केवल गरीबों और दलितों को सशक्त बनाया बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक गतिरोध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का उल्लेख करते हुए राजनाथ ने कहा कि वह उनकी बहादुरी के लिए राज्य के लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। यह बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे जिन्होंने हमारी मातृभूमि के गौरव को बचाया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और मै उनके बलिदान के लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए तीन चरणों28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को मतदान होना है और मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। भाजपा-जदयू गठबंधन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी

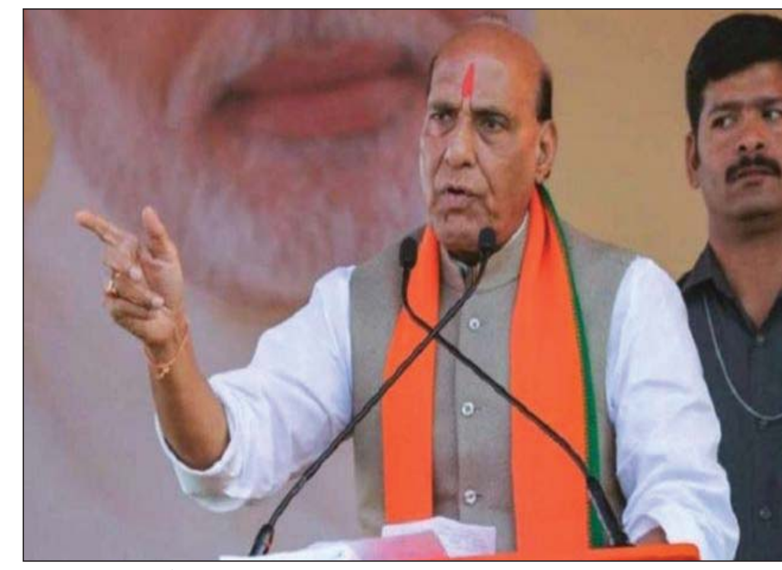

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर तथा बालीवुड के सेट डिजाइनर से राजनेता बने मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरा है। उनके मुकाबले में विपक्षी महागठबंधन मेंराजद, कांग्रेस और अन्य वामदल शामिल हैं। कुछ अन्य छोटे दल भी चुनाव मैदान में हैं।

सार समाचार

दिल्ली की जिला अदालतों में 15 जनवरी तक 'ई-जेल' की व्यवस्था होगी लागू

नयी दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि रिमांड, जमानत तथा वारंट संबंधी आदेश लेने के लिए जिला अदालतों और जेलों के बीच डिजिटल माध्यम से संपर्क की व्यवस्था 'ई-जेल' 15 जनवरी 2021 तक कार्यान्वित कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यिम प्रसाद की पीठ को बताया कि शुरुआत में यह सुविधा परीक्षण के तौर परचीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) और दो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) की तीन अदालतों में स्थापित की जा रही है। प्राधिकरण के वकील सुमेर सेठी ने कहा कि केंद्रीय कम्प्यूटर समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में 13 अक्टूबर को एक बैठक हुई थी जिसमें प्राधिकरण के सदस्य सचिव, कई विधिक अधिकारी और एनआईसी के अधिकारी शामिल थे। सेठी ने कहा कि ई-जेल व्यवस्था, 30 नवंबर तक सभी मजिस्ट्रेट अदालतों में स्थापित कर दी जाएगी। आपराधिक मामलों के अधिकार क्षेत्र वाली दिल्ली की अन्य जिला अदालतों में इसे 15 जनवरी 2021 तक लागू कर दिया जाएगा। पीठ ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 28 जनवरी को सुनवाईके लिए सूचीबद्ध कर दिया।

भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन, आयु संबंधी बीमारी से थीं ग्रसित

बेंगलुरु। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर (अवकाश प्राप्त) विजयलक्ष्मी रमणन का निधन हो गया है। वह 96 साल की थीं। उनके दामाद एस एल वी नारायण ने बताया कि विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम) से सम्मानित डॉ. रमणन का रविवार को आयु संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया। उन्होंने यहां अपनी बेटी के घर में अंतिम सांस ली। रमणन का जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। एमबीबीएस करने के बाद वह 22 अगस्त 1955 को सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थीं और उन्हें उसी दिन वायुसेना में स्थानांतरित कर दिया गया था।

बिहार चुनाव: योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर का किया जिक्र, बोले- भारत का हितैषी हर व्यक्ति पीएम मोदी के साथ खड़ा

जमुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत का हितैषी हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने से सबसे अधिक पीड़ा राहुल गांधी और असदुद्दीन औवैसी को हुई है। जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का हितैषी प्रत्येक व्यक्ति मोदीजी के साथ खड़ा है और उनके साथ कदम मिलाकर काम करना चाहता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके नेता पाकिस्तान की तारीफ करने में लगे हैं। ऐसे नेताओं से क्या देश के हित की कल्पना की जा सकती है ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे अधिक पीड़ा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को हुई। राजद नेता तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर तंज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, '' लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि आज 10 लाख नौकरी का वादा करने वाले लोगों ने 15 साल में कितनी नौकरियां दीं ? ''

प्रियंका का आरोप, कृषि कानूनों पर किसानों का दर्द नहीं सुन रही है सरकार

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों का दर्द नहीं सुन रही तथा उत्तर प्रदेश में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से बहुत कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब एमसएपी की गारंटी खत्म हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, ''भाजपा सरकार किसानों का हक मारने वाले विधेयकों पर सरकारी खाट सम्मेलन तो कर रही है लेकिन किसानों का दर्द नहीं सुन रही। उप्र में लगभग सभी जगहों पर किसान अपना धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से 800 रुपये कम 1000-1100 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं।'' उन्होंने सवाल किया, ''ऐसा तब है, जब एमएसपी की गारंटी है।

अपराध की नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बलों का किया जा रहा आधुनिकीकरण :अमित शाह

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार आतंकवाद, साइबर अपराध और सीमा सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने के लिए देश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैयार करने के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रही है। 'पुलिस स्मृति दिवस' पर यहां चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए शाह ने इसकी जानकारी दी। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए 10 पुलिसकर्मियों (सीआरपीएफ के) की याद में यह दिवस मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच वर्तमान में भी लद्दाख क्षेत्र में सैन्य गतिरोध जारी है।

कांग्रेस-लोजपा का घोषणा पत्र जनता को भरमाने के लिए झूठे वादों का पुलिंदा है: राजीव रंजन

पटना। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को केवल झूठे एवं अविश्वसनीय वादों पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और पेयजल योजना को लेकर के राज्य सरकार के युगांतकारी प्रयास को नकारते हुए नई योजना की चर्चा करने वाले कांग्रेसी नेताओं को यह जरूर बताना चाहिए कि आजादी के 70 साल में से बिहार में कांग्रेस और राजद ने मिलकर 58 वर्षों तक हुकूमत किया। फिर भी बुनियादी जरूरतें की बात हो चाहे हर घर बिजली की बात हो, पक्की नली गली की बात हो, नौजवानों को काम और औद्योगिक विकास या विस्तार का बात हो यह दोनों कहां सोए हुए थे।

ऐसी पार्टी जिसने आजादी के बाद से देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया एवं बिहार में भी उनका लंबे समय तक शासन रहा झूठे वादों पर आसमान से तारा तोड़कर लाने वाली जो भी पार्टियां हैं उनका अतीत और वर्तमान दोनों बिहार की जनता जानती है। और भविष्य में वह क्या करेंगे इसका आकलन उनके पूर्व में किए गए कार्यों के द्वारा बिहार की जनता ने कर लिया है। इसी कारण बिहार की जनता इस घोषणापत्र नामक छलावे के जाल में नहीं फंसने वाली है। प्रसाद ने कहा लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चिराग पासवान ने ढाक के तीन पात जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जिन विषयों को चिराग पासवान ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में उठाया है दरअसल उन विषयों पर बिहार में पहले से ही कार्य चल रहे हैं।

पीएम मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, बोले- पुलिसकर्मी बिना किसी हिचक के देते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि पुलिसकर्मी हमेशा बिना किसी हिचक के अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। 'पुलिस स्मृति दिवस' पर मोदी ने कहा, ''भयावह अपराधों को सुलझाने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपदा प्रबंधन में मदद करने से लेकर कोविड-19 से निपटने तक, पुलिसकर्मियों ने बिना किसी हिचक के अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है।''

उन्होंने कहा, ''हमें नागरिकों की सहायता के लिए उनके परिश्रम और उनकी तत्परता पर गर्व है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'पुलिस स्मृति दिवस' भारत में हमारे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को आभार व्यक्त करने का दिन है। कर्तव्यपालन के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बलिदान और सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा।

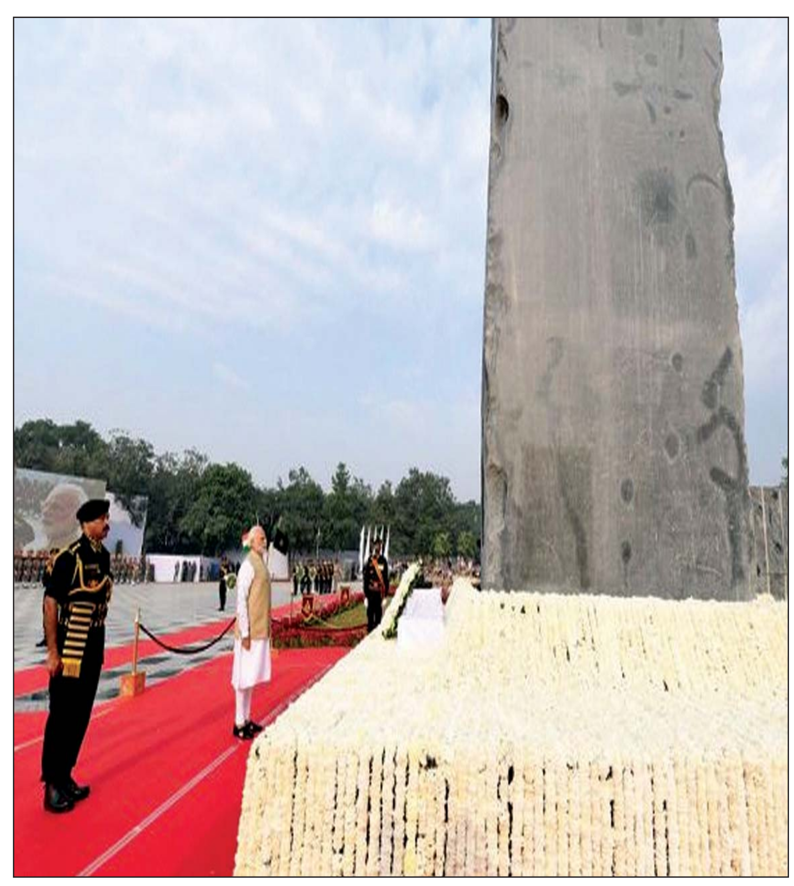

दिल्लीवासियों को जनवरी तक करना पड़ सकता है वर्क फॉर्म होम! प्रदूषण बनी बड़ी वजह

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टास्क फोर्स ने ईपीसीए को वर्क फॉर्म होम जनवरी तक जारी रखने की सलाह दी है। बता दें कि ईपीसीए सारे फैसले सीपीसीबी के तहत ही लेता है। सीपीसीबी ने मिटिंग के जरिए मौसम विभाग को लगातार प्रदूषण बढ़ने की चेतावनी दी है, और कहा है कि इसमें सुधार होने की कोई आंशाका नहीं है। इसी को देखते हुए सीपीसीबी ने ईपीसीए को वर्क फॉर्म होम जनवरी तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस दौरान आईटी कंपनियां वर्क फॉर्म होम कर रही है और इसे जनवरी तक जारी रखे जानें को कहा जा रहा है। गुरूग्राम की एक आईटी कंपनी में काम कर रहे पुनीत वसतकर ने कहा कि घर से काम करने के चक्कर में ऑफिस के सहयोगियों से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है और घर में केवल काम ही काम कर रहे है। पुनीत ने आगे कहा कि ऑफिस में जहां काम के साथ एंटरटेनमेंट भी होता था वहीं अब घर में केवल काम ही काम है। वहीं घर से काम करने में न ही ऑफिस जैसा माहौल है और न ही वैसी सीटिंग अरेंजमेंट्स। इन सबके कारण काफी मानसिक दबाव बनता जा रहा है। वहीं सीपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया की इस वक्त वर्क फॉर्म होम काफी फायंदेमंद साबित होगा। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी आएगी और साथ ही इस कोरोना महामारी संकट के बीच लोग सक्रंमण के खतरे से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा, सीपीसीबी मे तन्नक्क के नियमों का सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी है।

कांग्रेस का आरोप, त्यौहारों के समय विशेष ट्रेनों पर ज्यादा किराया वसूल रही सरकार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कांग्रेस ने त्यौहारों के समय भारतीय रेल की ओर से चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों पर पहले के मुकाबले 25-30 फीसदी अधिक किराया वसूले जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले तथा किराया और कम करे ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की जेब पर कम से कम बोझ पड़े। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि

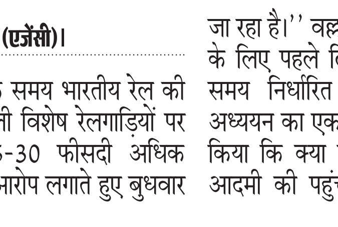

जब देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां और रोजगार खत्म हो गए हैं तो ऐसे में ज्यादा किराया वसूलना उचित नहीं है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''कोरोना वायरस संकट ने लोगों की आय को बहुत नुकसान पहुंचाया है और ऐसे में लोग त्यौहारों के समय कुछ खुशियां अपनों के साथ बांटने की कोशिश करेंगे। सरकार ने त्यौहारों के इस मौसम में जो 392 विशेष रेलगाड़ियां चलाईं हैं उन पर औसतन 25-30 फीसदी ज्यादा किराया वसूला जा रहा है।'' वल्लभ ने विभिन्न शहरों के बीच यात्रा के लिए पहले लिए जाने वाले और त्यौहारों के समय निर्धारित रेल किरायों पर तुलनात्मक अध्ययन का एक आंकड़ा पेश किया और सवाल किया कि क्या सरकार अब रेल को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर देना चाहती है?

उन्होंने कहा, ''हमारी मांग है कि सरकार रेल किरायों में इस बढ़ोतरी को तत्काल वापस ले तथा किराये को और कम करे ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की जेब पर कम से कम बोझ पड़े।''

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल त्योहारों के मद्देनजर 196 जोड़ी यानी 392 विशेष रेलगाड़ियां 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चला रही है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि त्यौहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया गया है। ये रेलगाड़ियां कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ आदि जैसे गंतव्यों के बीच चलेंगी ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर लोग अपने घर पहुंच सकें।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा का सीएए लागू करने संबंधी बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण: अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू करने के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि देश कोरोना वायरस महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है लेकिन भाजपा इस तरह के बयानों से उस तनाव को पुनः भड़काना चाहती है। गहलोत ने

ट्वीट में कहा, ''भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का संशोधित नागरिकता कानून लागू करने को लेकर बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना से पहले भी सीएए लागू करने को लेकर भाजपा की हठधर्मिता के कारण देश में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी और अब जबकि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, भाजपा इस तरह के बयानों से उस तनाव को पुनः भड़काना चाहती है।'' उन्होंने कहा, ''शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के बजाय, प्राथमिकता देश के समक्ष मौजूदा कोरोना संकट का एकजुटता से मुकाबला करते हुए जीवन बचाने की होनी चाहिए।'' उल्लेखनीय है कि नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की एक रैली में सीएए को लेकर कहा था कि जल्द ही राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जायेगा।

भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं: उद्धव ठाकरे

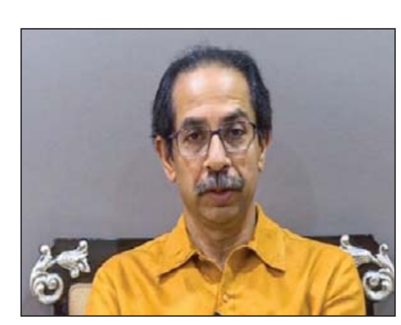

बेंगलुरु। (एजेंसी)।

उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राकांपा में शामिल होने के लिए एकनाथ खडसे के भाजपा छोड़ने पर बुधवार को कहा कि पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब वह सफलता के चरम पर पहुंच रही है, तो फिर उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं। ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि खडसे का शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाडी (एमवीए) परिवार में ''निश्चित तौर पर स्वागत'' है।

राज्य के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने घोषणा की कि महाराष्ट्र भाजपा में काफी समय से नाराज चल रहे खडसे शुक्रवार को राकांपा में शामिल होंगे। ठाकरे ने कहा कि खडसे उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में (भाजपा के) दिवंगत नेताओं, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के साथ पार्टी (भाजपा का) जनाधार बढ़ाया। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि खडसे की एक अलग पहचान है, वह एक योद्धा हैं और बेबाक बोलने वाले नेता हैं। ठाकरे ने कहा, ''जब एकनाथजी खडसे जैसा कोई नेता, जिन्होंने भाजपा की बुनियाद मजबूत की, पार्टी छोड़ते हैं तो भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे समय में उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं, जब वह सफलता के चरम पर पहुंच रही है।''

उन्होंने कहा कि यदि नींव का पत्थर ही निकलकर बाहर चला जाए, तो ऐसे में सफलता के चरम पर पहुंचने का क्या मतलब रह जाता है। मुख्यमंत्री, पिछले हफ्ते भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए उस्मानाबाद जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, ''इससे पहले, हमने (शिवसेना) राजग छोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल ने भी हाल ही में यह गठबंधन (राजग) छोड़ दिया। अब खडसे भाजपा के साथ नहीं हैं। इसलिए, भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए। भाजपा का पुराना मित्र होने के नेता उसे सतर्क करना मेरा कतर्व्य है।

ट्रेन के नीचे आकर 2 हाथियों की मौत के बाद ट्रेन के इंजन किया गया सीज

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

असम से आई खबर आपको जानवरों के खिलाफ होने वाली बर्बरता को कम करने में मदद कर सकती है। दरअसल, असम के अधिकारियों ने एक मालगाड़ी के इंजन सीज कर लिया है। यह इंजन उसी मालगाड़ी का है जिसने 27 सितंबर को लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एक हाथी और उसके बच्चे को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद हाथी और उसका बच्चा मर गया था। इसके बाद इस घटना को एक हत्या करार दिया गया। मालगाड़ी के इंजन को हत्या के लिए प्रयोग किया गया हथियार माना गया। यह पहला मौका है जब इस तरीके की चीजें देश में देखने को मिल रही है। असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ने भी कहा कि पटरियों पर हाथियों को मारना बंद होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग के रेलवे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में विफल नहीं होगा।

वन विभाग में प्रभागीय वन अधिकारी राजीब दास को इस मामले की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। राजीव ने कहा कि मालगाड़ी का इंजन हत्या के हथियार की तरह है। ऐसे में हमें अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियार को सीज करने की जरूरत थी। ऐसे में इस ट्रेन के इंजन को हम हथियार मानते हुए इसे सीज कर दिया है। इससे पहले असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वन विभाग में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रेल अधिकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई। इसके बाद रेलवे इस मामले में जांच को तैयार हुआ। रेलवे ने आंतरिक जांच कराई और लोको पायलट तथा उसके सहायक को निलंबित कर दिया था।

रेलवे को लिखित तौर पर कहा गया है कि वह लुमडिंग रिजर्व के अंदर ट्रेनों की गति धीमी रखें क्योंकि यहां जंगलों के हाथियों की आवाजाही लगातार पटरी पर बनी रहती है। उत्तर रेलवे ने यह दावा किया है कि इंजन को जब्त करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है। यह भी कहा गया कि इंजन को जब्त कर लिया गया और 45 दिनों के लिए रेलवे की कस्टडी में दे दिया गया। जब भी जांच में उस इंजन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि अगर रेलवे की हिरासत में रहते हुए इंजन के साथ कोई और घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे की ही होगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)